www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 04 | गोरखपुर, 21 जुलाई 2024 रविवार | पृष्ठ : 8 | मूल्य : 2

बांग्लादेश के कानून मंत्री अनिसुल हक बोलते हैं, विपक्षी जमात-ए- इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के छात्र विंग के सदस्य, आरक्षण विरोधी आंदोलन में कूद गए हैं। ये यही लोग हैं जिन्होंने हिंसा की शुरूआत की है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होनी है। छात्रों को भी मौका दिया गया है कि वो कोर्ट के सामने अपनी दलील रख सके। सवाल यह है कि जब देशव्यापी आग लगी हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर तत्काल सुनवाई क्यों नहीं कर सकती?

आरक्षण की आग में तपता बांग्लादेश

पूरे देश में गुरुवार को रेल और सड़क परिवहन सेवाओं को एहतियातन बंद कर दिया गया था। कोटा विरोधी प्रदर्शनकारियों ने ढाका के मोहाखाली में रेलवे लाइन को अवरुद्ध कर दिया था। देश के दूसरे हिस्से में भी रेल सेवा सुरक्षित नहीं दिखी। फार्मगेट इलाके में मेट्रोरेल पर हमला कर आगजनी की गई। काफी नुकसान के बाद हसीना सरकार ने हठ योग तोड़ा है। कानून मंत्री अनिसुल हक ने कहा कि मैं और शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी, कोटा, सुधार प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए कभी भी तैयार हैं। सरकार कोटा सुधार के खिलाफ नहीं है, हमने जस्टिस खंड-`कर दिलीरुज्जमां की अध्यक्षता में न्यायिक समिति का गठन भी कर दिया है। 18 दिनों से चल रहे आंदोलन में ऑफ द रिकार्ड 50 लोगों के मरने का अनुमान लगाया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बीजीबी (बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश) को चार जिलों ढाका, बोगरा, राजशाही और चटगांव में तैनात किया गया था । चटगांव, राजशाही, रंगपुर, बोगरा, मैमनसिंह समेत कई जगहों पर बड़े पैमाने पर झड़पें हुई हैं। चटगांव के शोलशहर और मुरादपुर में संस्कार, छात्र लीग और जुबो लीग के बीच हिंसक झड़पों में तीन लोगों की मौत हो गई। हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में केवल छात्र ही नहीं, राहगीर और कारोबारी भी आ रहे हैं। छात्र लीग, सत्तारूढ़ आवामी लीग की छात्र शाखा है, जिसकी स्थापना 4 जनवरी, 1948 को शेख मुजीबुर्रहमान ने की थी, तब उसका नाम, ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट लीग था। उसे काउंटर करने के वास्ते बांग्लादेश जातीयताबादी छात्र दल (जेसीडी) सड़कों पर दिखता है, जिसकी स्थापना, 1 जनवरी 1979 को बीएनपी के तत्कालीन नेता जनरल जियाउर्रहमान ने की थी। जमाते इस्लामी की छात्र शाखा, बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिबिर समय-समय पर इनके साथ खड़ी दिखती है। छात्र आंदोलनकारियों के बहाने क्या खालिदा जिया की बीएनपी को अपना खोया जनाधार मिलेगा ? विश्लेषक इसका उत्तर ढूंढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री अनिसुल हक बोलते

हैं, विपक्षी जमात-ए- इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के छात्र विंग के सदस्य, आरक्षण विरोधी आंदोलन में कूद गए हैं। ये यही लोग हैं जिन्होंने हिंसा की शुरूआत की है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होनी है। छात्रों को भी मौका दिया गया है कि वो कोर्ट के सामने अपनी दलील रख सके। सवाल यह है कि जब देशव्यापी आग लगी हो, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर तत्काल सुनवाई क्यों नहीं कर सकती?

ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की स वेबसाइट खोलते ही एक सूचना सामने आ वह जाती है, सारे वीजा अप्लीकेट नोट कर लें, सी आज 18 जुलाई को हमारा आईवीएसी सेंटर बंद र है। गुरुवार को सारे दूतावास और वाणिज्यदूत य कार्यालय बंद ही रहे। इन देशों ने अपने नागरिकों से को सावधान रहने, और फिलहाल बांग्लादेश ले नहीं आने की सलाह दे रखी है। कल 18 जुलाई को देशव्यापी बंद काफी हिंसक रहा है । ढाका उत्तर में पुलिस फायरिंग में चार लोगों की न मौत हुई है। मीरपुर में एक छात्र और आवामी लीग का एक कार्यकर्ता मारा गया। देशव्यापी म हिंसा में जिस पैमाने पर लोग घायल हुए हैं, मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बांग्लादेश टेलीविजन सेंटर को आग के हवाले कर दिया गया। छात्रों के दो समूहों के बीच देशव्यापी दंगा यदि आपने सुना और देखा नहीं होगा, तो बांग्लादेश सबसे बड़ा उदाहरण है। नाराजगी की एक और बड़ी वजह यह थी कि कोटे के अभ्यर्थी नहीं ई मिलने पर पद खाली रखने पड़ते थे। सरकार ने जनरल कोटे से पदों को में भरने की बात की थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। युवाओं ने 2018 में की भी कोटा सुधार आंदोलन शुरू किया था। उसके हिंसक और बेकाबू होने पर शेख हसीना सरकार तब भी झुकी थी। 11 अप्रैल, 2018 को शेख हसीना ने संसद में कहा, जब कोई कोटा नहीं चाहता तो कोटा नहीं होगा, कोटा सिस्टम अमान्य है। 2021 में कोटा रद्द करने के खिलाफ लोग कोर्ट चले गए। एक , जुलाई, 2024 को ढाका हाईकोर्ट के जस्टिस केएम कमरुल कादर और जस्टिस खिजिर हयात की बेंच ने अधिकारियों को आरक्षण व्यवस्था फिर से लागू करने का आदेश दिया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

संभवतः दुनिया के किसी भी देश में स्वंत्रतता सेनानियों के बेटे-बेटियों, पोते-पोतियों को आरक्षण देने की सुविधा नहीं है। यह असामान्य और अनोखी व्यवस्था है, जिस पर बांग्लादेश में शुरू में कभी सवाल नहीं उठाया गया था। मुक्तियुद्ध मामलों के मंत्री मुज्जम्मिल हक ने 25 मार्च, 2021 को 1 लाख 47 हजार, 537 स्वतंत्रता सेनानियों की सूची जारी की थी। इनमें से लगभग 50 हजार की इंट्री संदेहास्पद बताई जाती है। मुक्तिकामियों की तीन पीढ़ियों ने इन सुविधाओं का लाभ उठाया, अब चौथी और पांचवीं पीढ़ी को यही सुविधा देने की कवायद के पीछे शेख हसीना का वोट बैंक है। हसीना इसे स्थायी और भविष्य के लिए समर्पित देखना चाहती हैं। दरअसल, छात्र आंदोलन के दावानल को देखते हुए सतारूढ़ अवामी लीग को अपना सिंहासन डोलता नजर आने लगा है। आवामी लीग महासचिव ओबैदुल कादर ने कहा भी, हमारे अस्तित्व पर हमला किया गया है, हमें धमकी दी गई है। हमें इस स्थिति से निपटना होगा। कार्यकर्ता वार्ड दर वार्ड तैयार हो जाएं।

हिन्दुत्व के रंग में रंगी नौकरशाही

घुटने जबाब न दे गए होते तो मै भी एक बार कांवड़ यात्रा पर 1 जरूर जाता और आरिफ आम वाले से आम लेकर जरूर खाता। कावड़ यात्रा पर जाना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसानों और बेरोजगारों पर लाठियां बरसाने वाली यूपी सरकार कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा करती है। मिलाद-उल नवी का जुलूस निकलने वालों को ये सुख हासिल नहीं है। हासिल इसलिए नहीं है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन की और स से जारी उस आदेश के बारे में पढ़ा, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ स यात्रा के रास्ते में दुकाने लगाने वाले अपनी दुकानों के बाहर अपने नाम की पट्टियां भी लगाएं। मुझे अखबारनवीसी करते हुए चार दशक और लिखते पढ़ते पांच दशक हो गए हैं, ऐसा आदेश मैंने पहले देश के किसी हिस्से में नहीं देखा। मुझे लगता है कि यूपी में नौकरशाही दे पर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का असर इतना है कि नौकरशाही भी हिंदुत्व के रंग में रंग कर साम्प्रदायिक हो गयी है ।

कहने को मुख्यमंत्री हों या पुलिस अधीक्षक दोनों हिन्दुस्तान के संविधान की शपथ लेकर जनसेवा के लिए अपने आपको प्रस्तुत करते हैं किन्तु दुर्भाग्य ये है कि दोनों में से कोई भी संविधान के तहत चलने के लिए तैयार नहीं है। सबका अपना एजेंडा होता है। यथा राजा, तथा प्रजाअर्थात यदि सरकार का मुखिया साम्प्रदायिक होगा तो नौकरशाही अपने आप साम्प्रदायिक हो जाएगी। कोई भी सौ सिर का हो जाये इसे रोक नहीं सकता। कोई सरकार से सवाल नहीं करता की सरकार कि और से कांवड़ यात्रियों पर सरकारी खर्च से पुष्प वर्षा क्यों कराई जाती है और मोहर्रम के जुलूस या दूसरे धार्मिक जुलूसों के साथ ऐसा सम्मान क्यों प्रकट नहीं किया जाता ?

इस बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास सकवी नकवी का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों के आदेश की आलोचना की है। नकवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, 'कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जनम जात मत पूछिए, का जात अरुपात. रैदास पूत सब प्रभु के, कोए नहिं जात कुजात ।' नकवी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। वे भाजपा के कायर मुस्लिम नेता हैं। भाजपा ने जब लोकसभा चुनावों के समय एक भी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया था, तब नकवी कहाँ गए थे? उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज से भी गयी- गुजरी आवाज है। आजकल सरकारें आरएस-एएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत कीबात नहीं सुनती तो नकवी की बात को कौन सुनेगा? बेहतर हो कि नकवी भाजपा में तिल-तिलकर घुटने के बजाय भाजपा छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं। नकवी और उन जैसे भाजपा के तमाम मुस्लिम नेता 'सौ-सौ जूते खाएं, तमाशा घुसकर देखें' वाली स्थितियों में जो फंसे पड़े हैं। भाजपा के मुस्लिम नेताओं में कोई किरोड़ीमल मीणा नहीं है, जो अपमानित होकर सत्ता में रहने के बजाय अपना इस्तीफा देने का माद्दा रखता हो।

दरअसल सरकारों से सवाल करना अब अपराध की श्रेणी में आता है। ये सिलसिला केंद्र की तरफ से शुरू हुआ था और अब देशव्यापी हो गया है। सरकार या सरकारें 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा जरूर देतीं हैं लेकिन विकास उसी का करतीं हैं जिसने सरकार का साथ दिया है। असहमत समाज के लिए किसी भी साम्प्रदायिक सरकार के पास कोई सुविधा नहीं है। असहमत समाज के लिए सरकार के पास बुलडोजर है, नौकरशाही के ऊल- जलूल आदेश हैं। सरकारें निरंकुश हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेने के बजाय वे और आक्रामक और बेलगाम हो रहीं हैं

अल्पसंख्यक समाज की घोषित शत्रु डबल इंजिन की सरकारें -अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के खिलाफ जितना कर सकतीं हैं कर रहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से दो कदम आगे निकलकर असम की भाजपा सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून को ही रद्द कर दिया।

सरकार तो सरकार है, कुछ भी कर सकती है भले ही उसे ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार हो या न हो। संविधान डबल इंजिन की सरकारों के ठेंगे पर रहता है। हालाँकि संविधान से डबल इंजिन सरकारों का थोड़ा सा नाता बचा है। वे प्रतिपक्ष के संविधान बचाओ अभियान के जबाब में 'संविधान हत्या दिवस' जरूर मानाने की तैयारी कर रहे हैं। मै अक्सर टीवी की खबरें नहीं देखता, लेकिन कल संयोग से देखी तो मुझे पता चला की मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा का करीब 240 किलोमीटर का रूट पड़ता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण जिला है. यहां पुलिस के निर्देश के बाद दुकानों ने अपने-अपने नाम के साथ किस चीज की दुकान है, उसका नाम लिखकर पोस्टर लगा लिए हैं। 4 किसी ने अपने ठेले पर आरिफ आम वाला तो किसी ने निसार फ्ल वाला की पर्ची लिखकर टांग ली है। मुझे तो लगता है की सरकार और नौकरशाही से ज्यादा संविधान का सम्मान ये गरीब फल बेचने वाले आल्पसंख्यक करते हैं। इनका सम्मान किया जाना चाहिए। इस फरमान को लेकर विपक्षी नेता यूपी सरकार और यूपी पुलिस पर निशाना साध रहे हैं।

इस जनहसाप आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा कि जिसका नाम गुड्डु, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। पूर्व सीएम मायावती ने भी कहा कि नया सरकारी आदेश गलत परंपरा है, इसे वापस लिया जाए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान अछूत बना दिए गए हैं। पूर्व सांसद और प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर और तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप का आग्रह किया है।

4 कांवड़ यात्रा के रास्ते में कावड़ यात्रियों के लिए सरकार को मुस्लिमों को खड़े होने की इजाजत ही नहीं देना चाहिये। मुस्लिम दुकानदारों से नेमप्लेट लगाकर कारोबार करने से बेहतर है कि उन्हें कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते से हटा ही दिया जाय। सरकार कांवड़ यात्रियों के लिए खुद उचित मूल्य की सरकारी दुकानें खोले और उनके बाहर नोटिस चस्पा करे कि ये दुकाने केवल हिन्दुओं द्वारा संचालित है और यहां से केवल हिन्दू ही खरीद-फरोख्त कर सकते हैं। सरकारें जब शराब बेच सकतीं हैं तो हिन्दू कांवड़ियों के लिए अलग से दुकाने क्यों नहीं खोल सकतीं?

हिन्दू-मुसलमान करने का खमियाजा सरकार को आम चुनाव में भुगतना पड़ा था लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। सरकार पहले अयोध्या और हाल ही में बद्रीनाथ हारकर भी सबक लेने को तैयार नहीं है। सरकार तो अपना हिन्दू राष्ट्र मन ही मन बनाये बैठी है। उसका राजधर्म तो कांवड़ियों पर हेलीकाप्टर से फूल बरसाना है, तो है। आज की सरकारों के बारे में मेरे जैसा अंदना सा लेखक क्या लिख सकता है। ? ऐसी साम्प्रदायिक सरकारों के लिए गोस्वामी तुलसीदास छह सौ साल पहले ही लिख गए थे -

फूलें फले न बेत जदपि सुधा बरसे जलद ।
मूरख हृदयं न चेत जो गुरु मिले विरंच सम ॥

देश के कांवड़ यात्रियों को अग्रिम शुभकामनाएं। भवन भोलेनाथ उनका मनोरथ पूरा करें, क्योंकि बाकी के तमाम देवता तो सो गए हैं चार महीने के लिए। उनसे उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की करतूतें शायद देखी नहीं गयीं।

सर्वर फेल होने से राशन वितरण में परेशानी, कार्डधारक परेशान

परसामलिक (जीकेबी)। नौतनवा ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कोटेदारों को राशन वितरण करने में परेशानी हो रही है। सर्वर फेल होने के चलते राशन वितरण नहीं होने से कार्डधारक परेशान हैं। सर्वर की समस्या को लेकर कोटेदार और राशनकार्ड धारकों में नोकझोंक हो जाती है। कार्डधारकों को राशन के लिए काम छोड़कर दुकान का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नौतनवा ब्लाक क्षेत्र के कोहरगड्डी, मर्यादपुर, महरी, लुठहवा, तरैनी, असुरैना, बरगदवां निपनिया, रेहरा, विषखोप, पिपरा, खैरहवा दूबे, अहिरौली, जिगिना, शिवपुरी, भगवानपुर, महदेईया, चकदह, जमुहानी आदि गांवों में राशन वितरण में समस्या हो रही है। कोटेदारों ने बताया कि अप्रैल माह में जबसे नई ईपास मशीन ईवेईग कांटा लगा है। करीब तीन महीने से राशन वितरण के दौरान सर्वर सही काम नहीं कर रहा है। जिससे कार्ड धारकों को राशन देने में काफी दिक्कत हो रही है। कोटेदारों ने बताया की कार्डधारकों से नोकझोंक भी हो रही है। शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

क्षेत्र के राशनकार्ड धारक शकुंतला, संगीता, भरत, कांती, मीना, सरोज, ज्ञानमती, राम अवध, चंद्रमा, जगरनाथ, अनिल कुमार ने बताया कि राशन लेने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। बार बार कोटे की दुकान का चक्कर लगाना पड़ रहा है। आपूर्ति निरीक्षक विजय कुमार सहानी ने बताया कि सर्वर की समस्या को दूर कराने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।

पहली बारिश में बह गए सारे दावे

बस्ती (जीकेबी)। सुकरौली कुंवर बाजार में दो माह पहले सड़क का पुनर्निर्माण कराया गया था। यह सड़क पहली ही बारिश में छलनी हो गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने मई माह में इसका पुनर्निर्माण कराया है।

जानकारी के अनुसार, सुकरौली कुंवर सड़क का निर्माण करीब 15 साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कराया गया था। नवीनीकरण के बाद इसकी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई। पहली बारिश में ही मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। गिट्टियां उखड़ गई हैं। सड़क के साथ बनाई गई नाली की सफाई नहीं कराई गई। इससे बारिश के समय पानी भर जाता है। मानक विहीन कार्यों का खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है।

परिषदीय विद्यालय होने के चलते रोज सैकड़ों बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। इन्हें कीचड़ और खस्ताहाल रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है।

गांव के श्रीकुमार, अजय गुप्ता, बीरबल, संतकुमार प्रजापति आदि ने बताया कि निर्माण के समय ही गुणवत्ता को लेकर आवाज उठाई गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना।

प्रधान के प्रतिनिधि संजय गुप्ता ने कहा कि सड़क किनारे आबादी व पानी भरने की समस्या को देखते हुए यहां करीब 200 मीटर तक सीसी रोड का निर्माण कराने की जरूरत थी। पीडब्ल्यूडी अवर अभियंता महेंद्र यादव ने बताया कि मानक विहीन कार्यों की जांचकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कुत्तों का आरामगाह बना पीएचसी बनकटी का ड्रेसिंग रूम

बस्ती/बनकटी (जीकेबी)। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के तहत पीएचसी पर आयोजित शिविर में रविवार को ओपीडी में डॉ. कुमकुम राय मरीजों को परामर्श देते हुई मिलीं तो दूसरी ओर ड्रेसिंग रूम में कुत्ते आराम फरमाते हुए दिखे। अस्पताल में चौकीदार व अन्य कोई सुरक्षा कर्मी नहीं दिखा। इससे जन आरोग्य मेले के प्रति चिकित्सकों व कर्मियों संजीदगी समझी जा सकती है। पीएचसी की स्थिति का जायजा लिया गया तो इक्का-दुक्का कर्मचारी ही दिखे। डॉ. कुमकुम ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक 14 मरीज आए, जिन्हें परामर्श व दवाएं दी गईं। जानकारी के अनुसार, शासन ने अब 4 बजे तक आरोग्य मेले के आयोजन का फरमान जारी किया है, लेकिन मरीज न आने के कारण 2 से 3 बजे की बीच चिकित्सक केंद्र बंद कर घर चले गए। मुंडेरवा संवाद के अनुसार, पीएचसी पर डॉ. नीलम चौधरी मरीजों को परामर्श देते हुए कहा कि मानसून सीजन में मौसम कभी ठंड तो कभी गर्म रहता है। इससे शरीर में चिपचिपापन आ जाता है। ऐसे मौसम में त्वचा रोग, आंखों में इंफैक्शन और दस्त की सर्वाधिक आशंका बनी रहती है। बताया कि आरोग्य मेले में 14 मरीज पहुंचे। सीएचसी पर भी 11 मरीज पहुंचे। जहां डॉ. मेहनाज गनी, बबिता, अखिलेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। वाल्टरगंज प्रतिनिधि के अनुसार, पीएचसी पर डॉ. रवि वर्मा ने मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया। मौके पर उमेश चंद्र सिंह, कनिष्का चित्रगुप्त, कमल जीत, माधुरी, राजेंद्र आदि मौजूद रहे।

योगी और केशव आमने-सामने

केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में यह कह कर ठकराव का संकेत दिया था कि पार्टी हमेशा सरकार से बड़ी होती है। उन्होंने यह भी कहा था कि कार्यकर्ताओं की तरह उन्हें भी पीड़ा है। उधर अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर आरो लगा रही हैं कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग की नौकरियों को सामान्य वर्ग के लिए घोषित करती जा रही हैं। पार्टी के कई विधायक यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। नौकरशाही ने सरकार पर नियंत्रण कर रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। इन सारे बयानों को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। दूसरी ओर अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने स्वयं ही राजनीति के रिटायर होने की उम्र तय कर रखी है। इस बीच पत्रकार श्यामलाल यादव की पुस्तक 'एट द हार्ट ऑफ पावर : द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश' में यह भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने के लिए सन् 2021 के अंत से ही अभियान शुरू हो गया था। यह अभियान 2022 के आरंभ तक चला और इस सिलसिले में दिल्ली से लखनऊ तक कई बैठकें हुईं। लेकिन अंत में महसूस किया गया कि अगर उन्हें हटाया गया तो चुनाव में पार्टी को नुकसान हो जाएगा।

दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि योगी का कद इतना बड़ा है कि इन अभियानों का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भले अमित शाह यह महसूस करें के उन्हें मोदी का उत्तराधिकारी नहीं बनने देना है लेकिन जिस तरह से चुनाव अभियान में हर प्रदेश में योगी की मांग रहती है और वे हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के स्वाभाविक प्रतीक के तौर पर उभरे हैं उसे देखते हुए उन्हें हटा पाना संभव नहीं है। पार्टी में भले योगी की ज्यादा पकड़ न हो लेकिन उन्होंने अपने को एक सख्त प्रशासक के रूप में साबित किया है और उन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का वरदहस्त है। तभी संघ प्रमुख ने मोदी पर भले निशाना साधा हो लेकिन योगी पर कुछ नहीं कहा है। उल्टे गोरखपुर में शिविर के दौरान संघ प्रमुख और योगी लोगों की नजर में एक दूसरे के साथ नहीं दिखे लेकिन चर्चाओं में जरूर बने रहे।

लोकसभा चुनावों में तकरीबन तीस सीटों पर मिली हार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और सत्तारूढ दल भाजपा के भीतर घमासान मचा हुआ है। मुख्य धारा के अखबार और चैनल भले इसे छिपाने की कोशिश करें लेकिन अब यह बात पूरे देश की जुबान पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिर पर हार का ठीकरा फोड़कर उन्हें पद से हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। अगर विधानसभा के उपचुनावों में उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलते तो अभियान किसी परिणाम पर पहुंचेगा। इस अभियान में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से लेकर दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की शह बताई जाती है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरह की गतिविधि चल रही है उनसे संदेह बढ़ता ही जा रहा है। हाल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की है। इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की थी। लेकिन यहां पर इस बात की भी चर्चा करनी जरूरी हे कि भाजपा के भीतर एक अंत संघर्ष चल रहा है और वह डबल इंजन की सरकार और रामराज्य के दावे की कलई उतार देता है। अगर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है तो समझ लीजिए कि वे दोनों इंजन लंबे समय से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रामराज्य है तो समझ लीजिए कि प्रदेश में न तो भ्रष्टाचार कम हुआ है, न ही सि कानून का राज कायम हुआ है और न ही जनता का दैहिक, दैविक पि और भौतिक ताप समाप्त हुआ है। न ही प्रदेश के सभी जन आपस में प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। यह दिल्ली से लखनऊ तक चलने वाली शासन की मनमानी शैली का परिणाम है जहां मीडिया स्वतंत्र नहीं है और वह न तो विपक्ष की खबरें देता है और न ही असंतुष्ट और दुखी जनता 3 की पीड़ा को स्वर देता है। नतीजतन सरकारें भी जमीनी स्थिति से अनभिज्ञ रहती हैं और उन्हें सावन के अंधे की तरह चारों ओर हा हरा दिखता है। अयोध्या (फैजाबाद) से लेकर पूर्वांचल तक भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के पीछे जो एक बड़ी वजह है कि वह है मीडिया की स्वतंत्रता का समाप्त हो जाना। भाजपा यह जान ही नहीं पाई कि उसके नीचे से जमीन खिसक रही है। लेकिन इस चुनाव और उसके बाद मचे घमासान ने एक और संदेश दिया है और वह है हिंदू समाज के भीतर चलने वाले अंतसंघर्ष का। संघ परिवार अपने को बेहद समन्वयवादी बताकर यह दावा करता है कि उसने एक और अल्पसंख्यक समुदाय को डरा धमका कर उनके तुष्टीकरण को समाप्त कर दिया है और उन्हें हिंदू राष्ट्र के लिए तैयार कर लिया है तो दूसरी ओर वह यह भी दावा करता है कि उसके शासन में हिंदू समाज के भीतर जाति और वर्ण का कोई संघर्ष है ही नहीं। अब वह चाहे सवर्ण को मुख्यमंत्री बनाए चाहे चाहे पिछड़े को । कहीं से कोई विरोध नहीं होगा और न ही हिंदू एकता को कोई नुकसान होगा। एक तरह से संघ अपने को महान समन्वयवादी संगठन बताते हुए यह दावा करता है कि उसने जाति तोड़ने, जाति विनाश करने और स्त्री समता के समस्त संघर्षों को अप्रासंगिक कर दिया है क्योंकि उसने अपनी सोशल इंजीनियरिंग से ऐसी हिंदू एकता बनाई है कि अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है।

वह कहता भी है कि बाकी पार्टियां जातिवादी हैं एक वही है जो राष्ट्र के बारे में सोचता है और हिंदू समाज के बारे में चिंता करता है। लेकिन संस्था के शीर्ष पर खास जाति का व्यक्ति ही बैठ सकता है, यदि एक दो अपवादों को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पीडीए का फामूर्ला पेश किया और इंडिया समूह ने जाति जनगणना की मांग को आगे रखा उससे वास्तव में संघ परिवार का यह सिद्धांत लाया गया है। एक ओर वह पीडीए को फर्जी विचार बताने में लगा है तो दूसरी ओर उसी के लोग डीपीए यानी दलित, पिछड़ा

और अगड़ा समाज 13 की एकता के लिए यात्राओं की योजना बना रहे हैं। आज संघ परिवार उसी तरह से घमासान में उलझ गया है जिस तरह का घमासान उसने कभी मुलायम सिंह और कांशीराम के बीच करवाया था। संघ के सिद्धांतकारों ने बार बार यह साबित करने की कोशिश की थी कि 5 पिछड़ों और दलितों की पट नहीं सकती क्योंकि पिछड़े दलितों पर अत्याचार करते हैं। अब जब पिछड़े और दलित नए सिरे से संविधान और लोकतंत्र के नाम पर एकजुट हो रहे हैं और बसपा के जनाधार को नुकसान पहुंचाने के साथ भाजपा को भी हिला रहे हैं तो संघ परिवार में योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच घमासान मचा है। इस तरह का घमासान कभी कल्याण सिंह और उत्तर प्रदेश के सवर्ण भाजपा नेताओं राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र के बीच भी मचता था। जिसकी आंच अंटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच घमासान तक गई थी और कल्याण सिंह ने वाजपेयी को मुखौटा कहा था। बाद में वे पार्टी छोड़ने को भी मजबूर हुए थे।

वास्तव में हिंदू एकता का विचार न तो अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत पर आधारित हो सकता है और न ही दलितों पिछड़ों की उपेक्षा पर। वह सामाजिक समता और प्रेम पर ही आधारित हो सकता है। वह कट्टरता पर आधारित नहीं हो सकता। उसके लिए उदारता आवश्यक है। लेकिन संघ ने हिंदू एकता का ध्वज योगी जैसे कट्टर हिंदू नेता के हाथ में देकर दीर्घकाल में न सिर्फ समाज और राष्ट्र का अहित किया है बल्कि अपना भी अहित किया है। लेकिन एक लिहाज से संघ के भीतर यह घमासान बढ़ना शुभ है और उससे लंबे समय में भारतीय लोकतंत्र और समाज की उदार परंपरा समृद्ध होगी और शायद संघ भी कुछ सुधरे।

आतंकवाद का बदला चेहरा, रणनीति और ढांचा

कश्मीर समस्या का स्थायी निदान तभी मिल सकता है जब समस्या के वाह्य और आंतरिक दोनों कारणों को संतुलित किया जाए। इस दिशा में भारत ने सदैव सकारात्मक पहल की है। जम्मू-कश्मीर में आगामी चुनाव के मद्देनजर आतंकी घटनाएं और भी चिंतनीय हैं। स्थायी लोकतांत्रिक सरकार के गठन का औचित्य सुरक्षाङ्क सहयोगङ्क अवसर और समुन्नत जनसुविधाओं की निर्मिति पर आधारित होता है। आतंकवादियों के अशांति और हिंसा फैलाने के कुत्सित प्रयासों से निपटने के लिए भारत को उन्नत टेक्नोलॉजी का प्रभावी प्रयोग करने वाली आतंकरोधी रणनीति तैयार करनी होगी। सुरक्षा बलों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद का बदलता चेहराङ्क रणनीति और ढांचा। स्थानीय नागरिकों को विश्वास में लिए बगैर जम्मूझकश्मीर में शांति बहाल लगभग असंभव है। कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे बिना किसी निर्णायक फैसले तक नहीं पंहुचा जा सकता। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि इंसानियत और जम्हूरियत के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ जम्मूझ कश्मीर के लिए करने को तैयार हैं। अनुच्छेद ३७० हटने के बाद नये निवेशों और रोजगार उपलब्धता ने युवाओं में बेहतर भविष्य की संकल्पना को ठोस आधार दिया है। जम्मूझ कश्मीर में सकारात्मक परिवर्तन की पहल केंद्र सरकार की प्राथमिकता है॥। कश्मीरी लोगों के दिल-दिमाग को जीतने उनकी पीड़ा और उपेक्षा की भावनाओं को सहानुभूति प्रदान करना एवं उनकी चोटिल और कलंकित गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए राजनीतिक एवं सामाजिक अभियान की जरूरत है। जम्मू-कश्मीर के लोगों को इस सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि उनका सुरक्षित और गरिमापूर्ण भविष्य भारत के साथ है। आतंकवाद से निपटने के लिए हमें नियंत्रण और सशक्तिकरण दोनों के साथ बढ़ना होगा। व्यापक ब्लूप्रिंट के आधार पर ही जम्मूझकश्मीर की समस्याओं से निपटा जा सकता है। पुनर्स्थापित लोगों को मुख्यधारा में लाकर उनमें आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर को लेकर बातें बहुत हुई हैं अब समय निर्णायक और ठोस कदम उठाने का है। सेना के मनोबल को बढ़ाने का है। एक तरफ से कूटनीतिक प्रहार और दूसरी तरफ सेना द्वारा कार्रवाई। इस बार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ठोस और दूरगामी उत्तर देना समय की जरूरत है।

जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न उठाया है। जम्मू का जो इलाका शांत थाङ्क वह फिर से अशांत होकर आतंकवादी घटनाओं के निशाने पर है॥। केंद्र सरकार की लगातार कोशिश रही है कि जम्मूझकश्मीर में शांति बहाल हो और आम जन मुख्यधारा से जुड़े। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि एवं जम्मूझकश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी निरंतर प्रयासरत हैं। उनकी कार्यशैली बिना शोर किए अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विश्वास करती है। 2021 के बाद पुंछ-राजौरी और जम्मू के साथझ साथ पीर पंजाल रेंज के दक्षिण क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह बेहद चिंताजनक है। जम्मू क्षेत्र में 2023 और 2023 में सुरक्षा बलों पर कई हमले हुए। यह वर्ष इस अर्थ में और भी दुखद रहा है। दर्जनों जवान शहीद हुए हैं। इन आतंकवादी घटनाओं के पीछे कई संगठन और एजेंसियां सक्रिय हैं। इनके पार्श्व में पाकिस्तान और चीन को देखा जा सकता हैं। जम्मू के क्षेत्रों में आतंकवाद की पैठ सोचीझसमझी रणनीति का हिस्सा है। घाटी को आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। जम्मू तुलनात्मक रूप से शांत माना जाता रहा है। इसी का फायदा आतंकवादी संगठनों ने उठाया है। जब जम्मू में आतंकवाद धीरेझधीरे अपनी जड़ें जमा रहा था तब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। उनका सारा ध्यान घाटी पर केंद्रित था। दरअसल, आतंकवादी जम्मू में हमला करके संदेश देना चाहते हैं कि उनकी गिरफ्त में पूरा केंद्रशासित प्रदेश है। आतंकवादियों के लिए क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आतंकित करना लक्ष्य है। इसलिए पहले शांत इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कीं फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया। जम्मूझकश्मीर के आतंकवाद की समस्या को खत्म करने और देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए सरकार ने विवादास्पद अनुच्छेद ३७० हटाया। सरकार का फैसला एक हद तक सही और जरूरी भी था। लेकिन जम्मूझकश्मीर का आवाम सरकार की योजनाओं और नीतियों पर अपना विश्वास नहीं दिखला पाया। इन समस्याओं की जड़ें काफी गहरी हैं। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरू आत 1990 के दशक से होती है। तब से लेकर अब तक जम्मूझकश्मीर की धरती नापाक इरादों से रक्तरंजित होती रही है। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद जम्मूझकश्मीर में आतंकी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इनके निशाने पर आम जन है।

आखिर क्या है जम्मू को आतंक के निशाने पर लाने का मकसद। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जब कश्मीर में कमर तोड़ दी गई तब वह नये ठिकाने जम्मू में बनाने लगा। प्रश्न उठता है कि आखिर जम्मू ही क्यों? इसका उत्तर बहुत सरल है कि जम्मू भौगोलिक रूप से जंगलों से घिरा है जहां आतंकवादियों को आसानी से निशाना नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि इसके बहाने वे संपूर्ण जम्मू-कश्मीर में आतंक दिखलाना चाहते हैं। दहशत-हिंसा पैदा करना इनकी प्राथमिकता है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन तीर्थयात्रियों पर हमलों ने इनके मंसूबों को बतला दिया था। कश्मीर को छोड़ जम्मू को नया निशाना बनाने के पीछे कारण यह भी है कि केंद्र सरकार ने कश्मीर में सेना और विभिन्न एजेंसियों द्वारा आतंकवादी ढांचों पर इस तरह से शिकंजा कसा कि वे लगभग नेस्तनाबूद हो गए। उनके सभी नेटवर्क खत्म कर दिए गए जबकि पाकिस्तान की पहली पसंद कश्मीर ही रहा है। वहां अशांति और उबाल पैदा करना पाकिस्तान का पुराना शगल है। सुरक्षा एजेंसियां इस तथ्य से इंकार नहीं करतीं कि आतंकवाद को पुनर्जीवित करने में पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत हो सकती है। चीन का लक्ष्य संभवतः लद्दाख से सैनिकों को हटाने के लिए दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो। यह बात भी तय है कि आतंकवाद का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। सुरक्षा बलों की भूमिका स्थिति सामान्य करना है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित की जा सके

घूँघट की बगावत

21 जुलाई 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

▶ पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान-2024 ▶ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया प्रणि उद्यान में परिजात की पौध का पौधारोपण

'जनसहभागिता किसी भी अभियान को नई ऊंचाइयों पहुंचाती है'

गोरखपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान-2024 के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अश-ाफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में परिजात के पौध का पौधरोपण किया।

इस अवसर मुख्यमंत्री ने लोगो को सम्बोधित करते हुये कहा कि गत शनिवार को उ.प. ने 36.50 करोड़ वृक्षारोपण कर कीर्तिमान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आह्वान पर उ.प्र. में एक पेड़ मां के नाम लगभग हर मातृ शक्ति के नाम तीन-तीन पेड़ लगाने का कार्य अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है उन्होंने कहा कि इस वर्ष के गर्मी को लोग एक लम्बे समय तक याद करेंगे। 10 साल पहले भीषण गर्मी में गोरखपुर और आस पास के क्षेत्रों में तापमान 42 से 43 डिग्री होता था लेकिन इस वर्ष यह 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। यह अत्यधिक गर्मी, हीटवेव, लू, अतिवृष्टि, असमय बाढ़, सूखा यह सभी ग्लोबल वार्मिंग के लक्षण को प्रदर्शित करते है।

उन्होंने कहा कि गत वर्ष अक्टूबर माह में बाढ़ काफी आई थी जबकि अधिकतम 15 सितम्बर तक ही बाढ़ आती थी। इस वर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में ही उ0प्र0 के 24 जनपद बाढ़ ग्रसित है। यह चीजे हमें भविष्य के प्रति आगाह करती है और चेतावनी देती है कि सुधार करना होगा अन्यथा प्रकृति सुधार का क्रम अपने तरीके से करना शुरू करेगी। उसी चेतावनी को संज्ञान में लेते हुए उ0प्र0 ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 36.50 करोड़ वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम से जुड़कर इस धरती को हरा भरा करने, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए इस अभियान को अपने हाथो में लिया है। हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ा है और एक ही आह्वान सबका है कि पेड़ लगाना है और पर्यावरण को बचाना है। एक पेड़ मां के नाम के आधार पर पेड़ लगाओं पर्यावरण बचाओं इस आह्वान के साथ प्रदेश भर के लोग जुड़े है। प्रदेश में फलदार, इमारती छायादार, औषधि या सजावटी आदि प्रकार के 54 करोड़ के पौधे, वन विभाग, उद्यान विभाग की नर्सरी में है। जिसमें लगभग 37 से 38 करोड़ का उपयोग एक दिन में हो रहा है। शेष पौधों का क्रमिक रूप में उपयोग किया जायेगा।

विगत सात वर्ष में प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 168 करोड़ वृक्षारोपण.का नया रिकार्ड बना चुका है। 168 करोड़ वृक्षारोपण.प्रदेश सरकार ने जनसहभागिता और उ0प्र0 के विभिन्न विभागों के माध्यम से किया था इस-ाका परिणाम है कि वैश्विक संस्थाएं उ0प्र के इस महत्व को स्वीकार करती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्बन क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। लखनऊ में कार्बन क्रेडिट से जुड़े 25 हजार किसानों को पैसा भी मिला है कार्बन क्रेडिट के कारण 200 करोड़ रुपए उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि जो पेड़ लगाये गये है उसमें से 75 से 80 प्रतिशत पेड़ आज भी सुरक्षित है। वन वाटिकाएं आज भी है, कही नक्षत्र वाटिका, कही नवग्रह वाटिका, कही हरिशंकरी वाटिका और कही किसी अन्य नाम पर बनी वाटिकाओ के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। लखनऊ में एक नदी को पूर्न जीवित कराया गया है। आज से 50 वर्ष पहले गोमती नदी में एक संगम होता था। वह संगम कुकरैल और गोमती का था लेकिन 50 वर्षों में विकास की इस अंधी दौड़ में इसको पाट दिया था। भू माफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था। प्रदेश सरकार ने इसे बचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी और इसका परिणाम था कि आज हमने श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर सौमित्र वन और शक्तिवन के पुर्नगठन का कार्य करके कुकरैल क्षेत्र को लखनऊ में इको टूरिज्म के एक नये स्पाट के रूप में विकसित करने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह अभियान आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर में भी जूँ, काकोरी कांड के नायकों में एक अशफाक उल्लाह खां जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में राम प्रसाद बिस्मिल, चन्द्र शेखर आजाद, रोशन सिंह आदि क्रान्तिकारियों के साथ मिलकर देश की आजादी में अपने प्राण न्यौछावर किया था के नाम पर बने इस प्राणी उद्यान में वृक्षारोपण.के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में गोड़धोइया नाले को संरक्षण करके उसमें जल निकासी का स्थायी समाधान करके अतिक्रमण को हटाने का कार्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्राधिकरण के साथ मिलकर कर रही है। जब नालों से अतिक्रमण हटेगा तो हम शहरों को जल जमाव से मुक्त कर पायेंगे। आज गोरखपुर में इस प्राणि उद्याान में अलग अलग प्रकार के प्राणि और वन्य जीव है जो मनोरंजन के माध्यम बने हुए है साथ ही साथ ज्ञानवर्धक भी, वे हमें दिखानें का प्रयास करते है कि जब हम जीव सृष्टि के बात करते है तो केवल मनुष्य ही नही है, बल्कि जीव जन्तु भी है। जब इनमें बेहतर समन्वय होगा तो इसमें एक दूसरे की सुरक्षा भी जुड़ी होगी। वृक्षारोपण का यह कार्यक्रम इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है इस प्रकार का वातावरण मिल सके जो वनो के अंदर प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि यह वृक्षारोपण अभियान जनसहभागिता के साथ साथ वन, पंचायत, नगर विकास विभाग व अन्य सभी विभागों के साथ जुड कर आगे बढ़ाया जा रहा है। जन सहभागिता किसी भी अभियान को नयी ऊंचाईयों तक पहुंचाती है और इन्ही ऊँचाइयों का परिणाम है कि एक दिन में 36.50 करोड़ वृक्षारोपण का नया रिकार्ड बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

आवंटित खाद्यान्न का सुचारूरूप से वितरण सुनिश्चित कराएं जिलाधिकारी : मंडलायुक्त

गोरखपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जनपद में एक जुलाई 2024 को प्रचलित पात्र गृहस्थियों की कुल 2856144 यूनिटों के सापेक्ष 57122.88 कु. गेहूँ तथा 85684.32 कु. चावल का आवंटन माह सितम्बर 2024 हेतु (उठान माह अगस्त 2024) किया गया है। इस प्रकार एक जुलाई 2024 को प्रचलित 126392 अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु 17694.88 कु. गेहूँ तथा 26542.32 कु. चावल का आवंटन माह सितम्बर 2024 हेतु (उठान माह अगस्त 2024) किया गया है।

यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र गृहस्थियों हेतु खाद्यान्न का उठान एवं वितरण निम्न निदेर्शों के अनुसार सुनिश्चित कराया जाये। जनपदवार निर्धारित आवंटन के अनुसार खाद्यान्न का उठान निर्धारित रोस्टर के अनुसार कराया जाये। सम्बंधित उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी संलग्न विकास खण्डवार/क्षेत्रवार आवंटन आदेश के अनुसार दुकानवार आवंटन आदेश जारी करते हुए उचित मूल्य विक्रेताओं से तद्नुसार उठान/वितरण सुनिश्चित करायेंगे।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित प्रत्येक पात्र गृहस्थी परिवारों को उनके कार्ड पर माह सितम्बर 2024 में प्रति यूनिट दो किग्रा. गेहूँ तथा तीन किग्रा. चावल की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड धारक को 14 किग्रा गेहूँ तथा 21 किग्रा चावल प्रति कार्ड की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। सभी प्रवर्तन अधिकारी जांच कर निर्धारित मानक एवं दर पर पात्र गृहस्थी खाद्यान्न का वितरण चिन्हित पात्र गृहस्थियों में सुनिश्चित करायेंगे। वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर दोषी विक्रेताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ कठोर वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जाये। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा सम्बंधित केन्द्र प्रभारी खाद्यान्न शतप्रतिशत तौल कर ही उचित मूल्य विक्रेताओं को उपलब्ध करायेंगें।

शासनादेशानुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित वस्तुओं का सम्यक वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उप जिलाधिकारीगण को उत्तरदायी बनाया गया है।

अतः सभी उप जिलाधिकारीगण से अनुरोध है कि कृपया वे अपने पर्यवेक्षण में सघन जांच एवं निरीक्षण कराकर खाद्यान्न का समुचित वितरण पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में सुनिश्चित करावें। किसी प्रकार का कोई डाईवर्जन पाए जाने पर दोषी विक्रताओं के विरूद्ध कठोरतम् कार्यवाही करने के साथ-साथ वितरण व्यवस्था से सम्बद्ध अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। शासकीय निदेर्शों के अनुसार निरन्तर निरीक्षण एवं आकस्मिक जांच करा कर अन्त्योदय कार्डधारकों हेतु आवंटित खाद्यान्न का सुचाररूप से वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

एक दिवसीय चिन्हांकन 22 से

गोरखपुर। जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने बतया है कि जनपद के दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धार से जोड़ने हेतु ह्नदिव्यांगजन सशक्तीकरण विभागह्न द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद के समस्त विकास खण्डों एवं नगर क्षेत्र में एक दिवसीय वृहद चिन्हांकन शिविर का आयोजन 22 जुलाई से 14 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाले शिविर में निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया जायेगा। कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजनो को उनकी आवश्यकता के अनुसार कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों यथा-ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैशाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, लेप्रोसी किट, एम.आर. किट, कृत्रिम हाथ-पैर, कैलिपर्स आदि हेतु चिन्हित किया जायेगा। शादी-विवाह/प्रोत्साहन पुरस्कार योजना योजना अन्तर्गत शासनादेश के अनुसार पात्र दिव्यांग पति/पत्नी/दम्पत्ति जिनकी शादी दिनांक 01 अप्रैल 2023 से अब तक सम्पन्न हुई हो को प्रोत्साहन राशि क्रमशः 15 हजार/20 हजार/35 हजार की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु चिन्हित किया जायेगा। दुकान-निमार्ण/संचालन योजना योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजनों को रोजगार हेतु धनराशि 10 हजार एवं 20 हजार ऋण-अनुदान के रुप में प्रदान किये जाने हेतु चिन्हित किया जायेगा। दिव्यांग भरण पोषण/कुष्ठावस्था पेंशन योजना दिव्यांग/कुष्ठावस्था पेंशन योजना से वंचित दिव्यांगजनों को योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र दिव्यांगजनों को चिन्हित किया जायेगा। शल्य चिकित्सा/काक्लियर इम्प्लांट योजना योजनान्तर्गत 0 से 05 वर्ष के श्रवण-बाधित बच्चों का 06.00 लाख की धनराशि से निःशुल्क काक्लियर इम्प्लांट कराये जाने हेतु पात्र दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया जायेगा।

यू.डी.आई.डी. कार्ड योजना जिन दिव्यांगजनों के अब तब दिव्यांग प्रमाण-पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड नहीं बने उनके दिव्यांग प्रमाण-पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड चिकित्सकीय टीम द्वारा निर्गत की जायेगी।

मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक संपन्न

गोरखपुर। मण्डलायुक्त अनिल ढींगरा ने गोरखपुर मण्डल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुये कार्यों में सन्तोषजनक प्रगति न होने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और दुग्ध विभाग के अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकास/निर्माण कार्यों में विभाग आपसी समन्वय स्थापित करके यथाशीघ्र समयबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करें, इस पर किसी भी तरह की शिथिलता/लापरवाही पाये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो और कोई भी पात्र लाभार्थी इससे वंचित न रह पाये। उन्होंने हर घर नल योजना की धीमी प्रगति पर जल निगम के अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की।

उक्त निर्देश मण्डलायुक्त ने आयुक्त सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता एवं सीएम डैशबोर्ड से संबंधित मण्डल स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दिया। उन्होंने धारा 24 एवं धारा 80 के वादो के निस्तारण की समीक्षा करते हुये सभी जिलाधिकारियो को निर्देश दिया कि लम्बित वादो का निस्तारण तेजी से कराया जाये। उन्होंने निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिया कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान आपरेशन कायाकल्प, निपुण परीक्षा आंकलन, पीएम पोषण विद्यालय निरीक्षण तथा मध्यान्ह भोजन की समीक्षा करते हुये संबंधित विभाग को प्रगति लाने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कृषि विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पशुधन विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, समाज कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पंचायती राज विभाग आदि विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुये आवेदन पत्रों के सत्यापन कराने के कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया। उन्होंने शादी अनुदान योजना एवं जनपद देवरिया में लम्बित आवेदन के निस्तारण में प्रगति लाने का निर्देश दिया। पशुपालन विभाग के निराश्रित गौवंश के संरक्षण योजना में प्रगति लाने को कहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश, मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीना एवं वर्चुअल माध्यम से देवरिया, कुशीनगर तथा महाराजगंज के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी गण सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मण्डलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक

कृषकों की सभी शंकाओं का ससमय समाधान हो: कुंवर बहादुर

गोरखपुर। मण्डलायुक्त के निदेशानुसार अपर आयुक्त (प्रशासन) कुंवर बहादुर सिंह की अध्यक्षता में मण्डलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से एफपीओ/एफपीसी के सदस्य गण एवं कृषकों की सभी शंकाओं का ससमय समाधान करने का निर्देश दिया। बैठक में कृषि निर्यात के सम्बध में सहायक कृषि विपणन अधिकारी गोरखपुर मण्डल ओमप्रकाश ने प्रेजेंटेशन के द्वारा प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि इस नीति का विजन कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए ढांचे की व्यवस्था करना, कृषि फसलों एवं उत्पादों के निर्यात की क्षमता का सदुपयोग करना तथा कृषकों एवं अन्य हितधारकों की आय पर्याप्त रूप से बढ़ाना है और इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक उत्तर प्रदेश से कृषि निर्यात को दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि इससे अन्तर्गत मूल रूप से देशी व जैविक खेती से उत्पादित वस्तुओं को बढ़ावा देकर निर्यात योग्य बनाना है। सहायक कृषि विपणन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति उत्पादन और उत्पादों के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर केंद्रित है और क्लस्टर की पहचान उत्पादन, निर्यात में योगदान, निर्यातक के संचालन, प्रचलन की मापनीयता, निर्यात बाजारों के आकार और निर्यात में वृद्धि की क्षमता पर आधारित होगी। कृषि निर्यात उन्मुख क्लस्टर के गठन, पंजीकरण एवं निर्यात दायित्व पूर्ण होने पर विकास खण्ड की सीमान्तर्ग प्रथम 50 हे. से 100 हे. तक 05 वर्षों में 10 लाख रुपए एवं प्रत्येक 50 हे. अतिरिक्त क्षेत्र बढ़ने पर 06 लाख रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन, इसमें से प्रथम वर्ष 40 प्रतिशत एवं उसके पश्चात 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष आगामी 04 वर्ष तक निर्यात होने पर। उन्होंने बताया कि रोजगार सृजन करने और बढ़ावा देने के लिए एवं राज्य में निर्यात और फसल प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि निर्यात/पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय/सरकारी संस्थानों में पंजीकृत/अध्यनरत उत्तर प्रदेश के छात्रों को वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत (50 हजार रुपए की अधिकतम सीमा तक) तथा 15 महीने से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों हेतु फीस के लिए 01 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार के उच्च शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले राजकीय संस्थाओं को एक मुश्त 50 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जहां ट्रेन में चढने की होड लगी है

गायब होती कजरी गीत और सावन के झूले

जीवन शैली में बदलाव के कारण सावन में महिलाओं द्वारा गाये जाने वाली कजरी गीत और सावन के झूले गांवों से भी गायब हो रहे हैं। गांव में न दिखते झूले, न सुनाई देती कजरी।

जीवन शैली में बदलाव के कारण सावन में महिलाओं द्वारा गाये जाने वाली कजरी गीत और सावन के झूले गांवों से भी गायब हो रहे हैं। गांव में न दिखते झूले, न सुनाई देती कजरी। गांव के बुद्धिजीवी इसकी वजह अत्याधुनिक सुख सुविधा व मनोरंजन के बढ़ते साधन को मान रहे हैं। आषाढ़ माह लगते ही पेड़ों की डालियों एवं घरों की धरन में झूले पड़ जाते थे। दिन में बच्चे व बच्चियां और रात में नई नवेली महिलाएं झूले पर बैठ व दोनों तरफ से पेंग मारने के साथ कजरी गीत गा कर झूले का आनंद लेती थीं। यहां तक कि धान की रोपाई एवं सोहनी करते समय महिलायें पिया मेहदी मंगा दे मोती झील से, जाके सायकिल से ना..., घिर आई बदरिया, सजन घर नाही रे रामा और धीमे-धीमे बरसो ए बदरिया सजन घर नही आयो रे रामा... हरे रामा हमरो पिया पैलनिया खेलैं सेज कनिया ये हरी..., पिया सावन में झूला लगाय दs, हमके झूलाय दs ना...कजरी गाती थीं, तब पूरा सिवान आवाज से गूंज उठता था। अब तो इन बोलियों की पहचान गांव से भी धीरे-धीरे मिटती जा रही है।

बताते चलें कि सावन की तीज एवं अन्य पर्व स्वस्थ मनोरंजन के साधन तथा मेल-मिलाप के माध्यम हुआ करते थे। श्रद्धा, उमंग और खुशी के संगम से शुरू होने वाले इस महीने का चरम हरियाली तीज पर पहुंचकर समाप्त होता था। महिलाओं और युवतियों से बात करने पर उन्होंने इसे बीते दिनों की परम्परा बतायी, जबकि वृद्ध महिलाएं इस पर गंभीर हो गईं और बोलीं ए बबुआ जमाना बदल गइल।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजनी तहसील क्षेत्र के बिहारी बुजुर्ग निवासी कमलावती एवं भेऊसा दुबे की रेनू पांडेय ने बताया कि सावन के महीने में गांव की बेटियां अपने मायके आती थीं। मूसलाधार बारिश के बाद हल्की-हल्की बूंदों के बीच ही घर से निकल कर झूले झूलती थीं। दोनों महिलाओं ने बताया कि सावन के महीने में शायद ही कोई घर ऐसा बचा रहता था, जहां लड़कियों और नव-विवाहिताओं को कजरी गाते न देखा जाता रहा हो। मगर अब सारी बातें गांवों में बीते जमाने के किस्से कहानियां ही बन कर रह गई हैं। वहीं उम्रदराज महिलाओं ने बताया कि बाग-बगीचों में अब सावन के गीत नहीं गूंजते, हरियाली तीज की परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसी के साथ उस दौरान गाए जाने वाले गीत भी।

मिट्टी में मिलते जा रहे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के अरमान

मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रोजगार नहीं है, न ही कृषि करने के लिए इनके पास भूमि है। और न अन्य साधन, जिससे आय का आवक हो पाए। यह जैसे-तैसे करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। मौजूदा दौर में एल्युमीनियम, थमाकील व प्लास्टिक बर्तनों का खूब चलन चला है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे पूर्वज अपने समय में मिट्टी, लोहे व काँसे के बने बर्तनों का उपयोग करते थे। इसलिए उन्हें मौजूदा दौर की बीमारियाँ नहीं हुईं। यदि आप भी, अपने पूर्वजों की भाँति स्वस्थ्य जीवन-यापन करना चाहते हैं तो, मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग भोजन बनाने के लिए करें, ताकि आपके स्वस्थ्य के साथ ही इन कुम्हारों की माली हालत में सुधार हो सके।

आधुनिक फ्रिज और एसी ने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। ये मिट्टी के बर्तन बनाकर रखतें हैं लेकिन बिक्री न होने की वजह से खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। परिवार कैसे चलेगा। कोई भी मटके खरीदने नहीं आ रहा है। धंधे से जुड़े लोगों ने ठेले पर रखकर मटके बेचने भी बंद कर दिए हैं। देश भर में प्रजापति समाज के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। कुम्हार अपना पुश्तैनी काम छोड़ नहीं सकते. इसलिए उनके पास मिट्टी के बर्तन और गर्मी के दिनों में घड़े बेचने के अलावा कमाई का दूसरा विकल्प नहीं है. हालात ये हैं कि अब कुम्हार परिवार अपने काम को जिंदा रखने के लिए कर्ज लेकर व्यवसाय कर रहे हैं. लेकिन इससे भी इनकी लागत नहीं निकल रही. कुम्हार (कुंभकार) जाति के लोग मिट्टी से ही अपना रोजी-रोटी एवं जीवन-यापन करते हैं। कुम्हार शब्द, कुम्भकार से निकला हुआ प्रतीत होता है, जिसका अर्थ कुम्भ, यानि घड़ा बनाने वाला होता है। इन्हें कुम्भार, प्रजापति, प्रजापत, घूमियार, घूमर, कुमावत, भांडे, कुलाल या कलाल आदि नामों से भी अलग-अलग प्रदेशों में जाना जाता है। कुम्हारों की हस्तकला ही, उनके रोजगार का साधन होता है। कुम्हार अपने हाथों से मिट्टी की वस्तुएं बनाते हैं।

कुम्हार मिट्टी से वस्तुएं बनाने के लिए काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेत व राख आदि को एक साथ मिलाकर, पानी डाल कर अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद चाक (चकरी) में मिट्टी को रखकर उनको आकार देते हैं, और भिभिन्न-भिभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। देवी-देवताओं की मूर्तियां, दीया, बोरा, बैल, करसा, क्लास, ठेकुआ, पुरा, मर्की, ओम, देवा, चूल्हा व बच्चों के खिलौने। मिट्टी के बर्तन पकने के बाद, उनको नजदीकी बाजार एवं चौक-चौराहों में बेचने के लिए ले जाते हैं। और उसके बाद, उसी वस्तुओं के पैसे से जो आमदनी उनको प्राप्त होती है, उसी से यह अपना जीवन-यापन और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इन मिट्टी के बर्तन या खिलौने का मूल्य उतना ज्यादा नहीं रहता, जीतना उसमें मेहनत लगता है। और-तो-और लेने वाला व्यक्ति भी, वस्तुएं लेने पर मोलभाव करके, उसमें पैसा कम करवा ही लेता है।

इन कुम्हारों का रोजगार उतना अच्छा नहीं रहता। क्योंकि, पहले के समय में, सभी लोग मिट्टी के बर्तन व मिट्टी के वस्तुएं उपयोग करते थे। लेकिन अभी, वर्तमान के समय में, मिट्टी के बर्तनो को लोग नहीं के बराबर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि, सभी लोग स्टील के बर्तन, फाइबर के बर्तन आदि का अधिक यूज करते हैं। जिससे इनकी आमदनी, पहले के समय से कम होती है। गणेश पक्ष, दुर्गा पक्ष व विश्वकर्मा पक्ष आदि में ही इन लोगों को थोड़ी आमदनी हो पाती है और बाकी समय में इनको एक दिन में 100 से 200 रुपये भी मिलना मुश्किल हो जाता है। बहुत से कुम्हार, आमदनी अच्छी ना होने के कारण, मिट्टी के वस्तु बनाना छोड़ दिए हैं। और कुछ अन्य काम, अपने जीवन-यापन करने के लिए पकड़ लिए हैं और उसी में लगे हुए हैं। वह लोग इस काम को और करना नहीं चाहते। क्योंकि, इसमें मेहनत अधिक और आमदनी कम है।

वर्तमान में कुम्हारों का स्थिति बहुत ही खराब है। क्योंकि, पहले जैसा अभी के समय में लोग मिट्टी के समान उपयोग करना बंद कर दिए हैं। इस कारण, इनके पास जो बना हुआ वस्तु भी रहता है। वह भी बिक नहीं पाता है, जिससे इनको नुकसान ही उठाना पड़ता है। बाकि मिट्टी के वस्तुएं, अपने सीजन में ही बिक पाते हैं। बाकी समय इनका बिकना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी व पानी की समस्या ने इस धंधे की कमर तोड़ दी है। पहले इस व्यवसाय के लिए यह गांव काफी चर्चित था। लेकिन समय बीतते के साथ सब कुछ खत्म होने लगा है। गांव में कच्चे मकान की संख्या काफी कम हो गई है। जिस कारण छत में लगने वाले खपड़े की बिक्री नहीं के बराबर होती है। अब इस धंधे से लाभ नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी मिट्टी के लिए होती है। पहले वर्षों से मिट्टी वन विभाग की जमीन से लाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में इस पर रोक लगा दी गई है। पानी की समस्या एवं कोयले के दाम में बढ़ोत्तरी। जिसने इस धंधे की कमर तोड़ कर रख दी है। परिवार के चार सदस्यों की कड़ी मेहनत के बाद एक दिन में ढाई सौ खपड़े का निर्माण हो पाता है। जिसे पकाकर तीन हजार रुपए में बेचा जाता है। लागत के अनुसार उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा इनके पास और कोई दूसरा रोजगार नहीं है, न ही कृषि करने के लिए इनके पास भूमि है। और न अन्य साधन, जिससे आय का आवक हो पाए। यह जैसे-तैसे करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। मौजूदा दौर में एल्युमीनियम, थमाकौल व प्लास्टिक बर्तनों का खूब चलन चला है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे पूर्वज अपने समय में मिट्टी, लोहे व काँसे के बने बर्तनों का उपयोग करते थे। इसलिए उन्हें मौजूदा दौर की बीमारियाँ नहीं हुईं। यदि आप भी, अपने पूर्वजों की भाँति स्वस्थ्य जीवन-यापन करना चाहते हैं तो, मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग भोजन बनाने के लिए करें, ताकि आपके स्वस्थ्य के साथ ही इन कुम्हारों की माली हालत में सुधार हो सके।

-प्रियंका सौरभ

समाज में बुजुर्गों की अनदेखी व दुर्व्यवहार के बढ़ते मामले

देश में वृद्धों के साथ उपेक्षा, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना बढ़ती जा रही है, बच्चे अपने माता-पिता के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते, वे उनके जीवन-निर्वाह की जिम्मेदारी भी नहीं उठाना चाहते हैं, जिससे भारत की बुजुर्ग पीढ़ी का जीवन नरकमय बना हुआ है, वृद्धजनों की पल-पल की घुटन, तनाव, जीवन-निर्वाह करने की जटिलता एवं उपेक्षा को लेकर समय-समय पर जहां न्यायालयों ने अपनी चिन्ता जतायी है, वहीं सरकार ने कानून बनाकर बुजुर्गों को उन्नत एवं शांति देने के प्रयास किये हैं, लेकिन इसके बावजूद वृद्ध लोगों का जीवन कष्टमय एवं जटिल बना हुआ है। वृद्ध माता-पिता की देखभाल एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अदालतों में गुजारा-भत्ते से जुड़े विवाद बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिये बाध्य करने वाले 2007 के कानून में बदलाव लाकर, इसका दायरा बढ़ाने के मकसद से नये कानून लाने की तैयारी में है। माता-पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े वर्षों पुराने कानून को प्रभावी व व्यावहारिक बनाने की कोशिश निश्चित रूप से सामाजिक एवं पारिवारिक ताने-बाने में वृद्धों को सम्मानजनक जीवन देने की सार्थक एवं सराहनीय कोशिश है। इस समय देश में करीब 10.5 करोड़ बुजुर्ग लोग हैं और 2050 तक इनकी संख्या 32.4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारत सहित 64 ऐसे देश होंगे जहाँ 30 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की होगी। एकल परिवार के दौर में बुजर्गों की देखभाल और भरण पोषण एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रही है ऐसे में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुजुर्गों की देखभाल के लिये मेंटिनेंस ऐंड वेलफेयर ऑफ पैरंट्स ऐंड सीनियर सिटिजन ऐक्ट 2007 में संशोधन की पहल की है, नये बिल के मुताबिक अब घर के बुजुर्गों की जिम्मेदारी सिर्फ बेटे ही नहीं, बल्कि बहू-दामाद, गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बेटे और बेटियों की भी होगी। बिल लाने का मकसद बुजुर्गों का सम्मान सुनिश्चित करना है। पहले वृद्ध माता-पिता अपनी संतानों से दस हजार रुपये तक का गुजारा भत्ता पाने के हकदार थे। बताया जा रहा है कि नये विधेयक के अनुसार अब माता-पिता का गुजारा भत्ता बच्चों की आर्थिक हैसियत से तय होगा। वहीं बच्चों के साथ कटुता कम करने के प्रयासों में माता-पिता व बुजुर्गों को त्यागने अथवा दुर्व्यवहार पर बच्चों को दी जाने वाली सजा में कमी करने की भी तैयारी है। ऐसा सामाजिक संगठनों से विमर्श के बाद किया गया है। क्योंकि लंबी सजा से माता-पिता और बच्चों के संबंधों में ज्यादा खटास बढ़ती है। कहा जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में इस विधेयक को पेश कर सकती है। दरअसल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों की देखभाल से जुड़े 2007 के कानून में बदलाव की पहल तब की, जब समाज में बुजुर्गों की अनदेखी व दुर्व्यवहार के मामले तेजी से बढ़े हैं। भारतीय संस्कृति एवं सभी धार्मिक ग्रंथों में माता पिता को भगवान का रूप माना गया है और उनकी निःस्वार्थ सेवा करने की बात कही गयी है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग अपने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करना तो दूर उल्टा उन्हें परेशान करते रहते हैं। इसलिये विभिन्न राज्यों की सरकारें बुजुर्ग आत्म-सम्मान के लिये नये कानून बना रही है। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार अब बुजुर्ग मां-बाप की संपत्ति हड़प कर उन्हें बेदखल करने वाले बच्चों के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत माता-पिता की संपत्ति हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकलने वाले बेटे-बेटियों की खैर नहीं होगी। कुछ दूसरी तरह से असम सरकार ने वृद्धों की उपेक्षा पर विराम लगाने की दृष्टि से ही राज्य कर्मचारियों के लिए नवंबर में दो विशेष अवकाश शुरू किए हैं, ताकि वे अपने माता-पिता या सास-ससुर के साथ समय बिता सकें। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी घोषणा में परिवार के महत्व पर जोर दिया। 6 और 8 नवंबर को मिलने वाली ये विशेष छुट्टियां कर्मचारियों को उनके बुजुर्ग माता-पिता या सास-ससुर से जुड़ने के लिए हैं। इसका उद्देश्य परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सम्मान और देखभाल दिखाना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी घोषणा में परिवार के महत्व पर जोर देते हुए कहा है किमाता-पिता का आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। एक आदर्श नागरिक के रूप में, अपने माता-पिता की भलाई सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। असम सरकार ने पूर्व में राज्य विधानसभा ने असम कर्मचारी माता-पिता जिम्मेदारी एवं जवाबेदही तथा निगरानी नियम विधेयक, 2017 या प्रणाम विधेयक भी पारित कर चुकी है। इसका मकसद यह सुनिश्चत करना है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वृद्ध हो रहे माता-पिता या शारीरिक रूप से अशक्त भाई-बहन की देखभाल करें नहीं तो उनके वेतन से पैसे काट लिए जाएंगे। पूरे देशभर के लोग इस कानून को असम सरकार का एक अच्छा कदम बताया। नियमों के तहत अगर कोई व्यक्ति (सरकारी कर्मचारी) उसपर निर्भर माता-पिता की देखभाल नहीं करता तो उसके कुल वेतन का 10 प्रतिशत हिस्सा काट लिया जाएगा और वह राशि माता-पिता के खाते में डाल दी जाएगी। दिव्यांग (शारीरिक रूप से अशक्त) भाई-बहन होने की स्थिति में वेतन से 15 प्रतिशत तक हिस्सा काट लिया जाएगा। अब केन्द्र सरकार द्वारा 2007 के कानून में बदलाव लाकर, नये विधेयक में इससे जुड़े कानून की व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, मंत्रालय ने कानून में बदलाव की पहल वर्ष 2019 में कर दी थी। इसी साल लोकसभा में एक विधेयक भी पेश किया गया था। इसके व्यापक पहलुओं की पड़ताल के लिये विधेयक को बाद में संसदीय समिति के पास भेज गया था। संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक बार फिर एक विधेयक को संसद में पेश किया था। लेकिन वह पारित नहीं हो पाया था। कालांतर 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के कारण विधेयक निष्प्रभावी हो गया था। जिसके बाद अब सरकार नये सिरे से इस विधेयक को संसद में लाने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में कई नये प्रावधानों को जोड़ा गया है। विधेयक में प्रत्येक जिले में बुजुर्गों की गणना, मेडिकल सुविधाओं से लैस वृद्ध आश्रम व जिला स्तर पर एक सेल गठित करने जैसे प्रावधान हैं। संतान द्वारा बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पूरा न करना गरिमा के साथ स्वतंत्र जीवन जीने जैसे मानवाधिकारों का हनन है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। वृद्धों की उपेक्षा एवं दुर्व्यवहार के इस गलत प्रवाह को रोकने की दृष्टि से नया कानून प्रभावी कदम है, इससे बच्चों की अपने माता-पिता की उपेक्षा पर विराम लग सकेगा। सभी के लिये बुजुर्ग पीढ़ी के लिए सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी ही चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सके। वृद्धों को बंधन नहीं, आत्म-गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सुसंस्कृत परिवार परम्परा पर काला दाग है, यह आदर्श-शासन व्यवस्था के लिये भी शर्म का विषय है।

कर्नाटक सरकार का आरक्षण मसला : आ बैल मुझे मार

कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नें जो अंधेरगर्दी मचाई है उसके जद में यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा आए है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नें यूपी और बिहार के लोगो का रोजगार छीन लिया है और इनमें सबसे अधिक दलित और पिछड़े तबके के लोग ही होंगे जो निजी कम्पनियों में काम धंधा कों लेकर दक्षिण भारत का रुख करते है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नें देश भर के लाखों लोगो कों बेरोजगार किया है और जब चुनाव में जायेंगे तो बेरोजगारी पर सबसे लम्बे चौड़े भाषण देंगे। कर्नाटक के तमाम निजी कंपनियों में राज्य के स्थानीय लोगो को 100% तक आरक्षण होगा। प्रबंधन स्तर पर 50% और गैर प्रबंधन स्तर पर 70% नौकरियां कन्नड़ भाषियों को ! ग्रुप सी और ग्रुप डी में शत प्रतिशत आरक्षण ! कांग्रेस सरकार की कैबिनेट ने विधेयक पर मुहर लगाई जिसके बाद यूपी बिहार और शेष भारत के लाखों युवाओं को राज्य छोड़ना पड़ेगा ! अब इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा वो भी समझिये, बर्बाद हो सकता है बंगलुरू स्थित देश का सबसे बड़ा आईटी हब ! शिफ्ट हो सकते है इंफोसिस , विप्रो , हॉल , टीसीएस , आईबीएम, सिस्को आदि क्यूंकि बड़ी कंपनियों में देश के 35% युवा कर्नाटक में काम करते हैं ! ऐसी घोषणाओं से बंद हो सकती हैं ये गोल्ड ग्रुप की सभी कंपनियां ! जिसे कन्नड़ भाषा नहीं आती , वह राज्य से बाहर जाएगा ! बेंगलुरू के साथ साथ मैसूर , मैंगलोर , चित्रदुर्ग आदि स्थित कंपनियों , सैकड़ों इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेजों का भविष्य अंधेरे में !

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विश्लेषक एवं पत्रकार पंकज सीबी मिश्रा के अनुसार, कर्नाटक में बोए बीज की शाखाएं कांग्रेस शासित तेलंगाना और इंडी गठबंधन के तमिलनाडु में भी फूटकर निकल सकती हैं । महाराष्ट्र पहले ही मराठी मानुष और मराठी आरक्षण का विष पिए बैठा है । कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर लोगो कों कोर्ट जाना चाहिए यद्यपि कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और विधेयक संभवतः वर्षाकालीन सत्र में पेश न हो पाए। लेकिन सिद्धरमैया सरकार ने गलत बुनियाद रख दी है । पहले मुस्लिमों को 4% आरक्षण का लॉलीपॉप पकड़ाया और प्रदेश के आईटी और कंप्यूटर सैक्टर को तबाह करने की शुरूआत हुई । जाहिर है कंपनियां कर्नाटक से उसी तरह भागेंगी जैसे बंगाल से टाटा को भागना पड़ा था । आरक्षण , जाति आरक्षण , जातिगत जनगणना के बाद कांग्रेस का यह नया फरमान अजीब है । क्या आप जानते हैं कि कर्नाटक उन कुछ राज्यों में शीर्ष पर है जहां बड़े पैमाने पर स्टार्ट अप शुरू हुए हैं ? इन सभी में राज्य के बाहर से आए युवाओं की संख्या सबसे अधिक है । 100% तक कन्नड़ आरक्षण की आग को न रोका गया तो भाषाई और प्रांतीय आधार पर यह देश भर में फैल जाएगी । याद रखिए सरकारी संस्थानों का आरक्षण बढ़ाने के परिणामस्वरूप पांच करोड़ लोग देश छोड़ गए हैं । आरक्षण का यह कोढ़ प्राइवेट सैक्टर में फैला तो देश से प्रतिभाओं का पलायन बेतहाशा बढ़ जाएगा । युवा शक्ति का पलायन भारत को जापान की तरह बूढों का देश बना दे , इससे पहले संभालना होगा । विशेषकर कांग्रेस जैसे बड़े दल को जिसके नेता आरक्षण के नाम पर सपा बसपा राजद और डीएमके जैसे दलों को मात देने पर आमादा हैं । निजी क्षेत्र विशेष रूप से प्रतिभाओं का चयन करते हैं । इनमें जाती या क्षेत्रीय आरक्षण जैसा कोई सवाल कभी नहीं उठा । कर्नाटक की तर्ज पर यह आग और राज्यों में फैलने का अर्थ प्राइवेट सैक्टर को बर्बाद करना होगा । ऐसे तो भारत आ रहे बड़े बड़े उद्योग किसी और देश का रुख कर लेंगे ।

पंकज कुमार मिश्रा,
जौनपुर यूपी

प्रश्न प्रशासनिक व्यवसथाओं की साख का...

हमारी सभ्यता सदियों पुरानी है। इसकी समृद्धि का गुणगान इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसके बावजूद समाज के विभाजन ने इतना जर्जर कर दिया कि हम हजारों साल तक कभी मुगलों तो कभी अंग्रेजों के गुलाम बने रहे। दुःख की बात है कि जाति, पंथ और क्षेत्र के नाम पर लगभग वैसा ही विभाजन आज हमारी प्रशासनिक सेवामें प्रवेश कर चुका है। राजनीति और नौकरशाही का गठजोड़ इसके लिए सबसे जयादा जिम्मेदार है। इससे छुटकारा पाने के लिए देश की नौकरशाही के मौजूदा रूप यानी उसकी भर्ती से लेकर ट्रेनिंग और सुविधाओं में तुरंत सुधार करना होगा। नोकरी की सुरक्षा और सुविधाएं ही बार-बार पूजा खेड़कर जैसे अधिकारियों को जन्म देती हें। यदि देश को कोई सही संदेश देना हे तो पूजा खेड़कर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशिक्षण अवधि के दौरान बर्खास्त करने में कोई सेवा नियम आड़े नहीं आता है। इसके साथ ही सरकार ने पूजा खेड़कर पर लगे आरोपों की जांच के लिए जो समिति बनाई गई है, उसका यह दायित्व भी बनता है कि उनके मेडिकल सर्टिफिकेट से लेकर ओबीसी सर्टिफिकेट देने के मामलों की जांच करे, क्योंकि यह प्रकरण यूपीएससी और कार्मिक मंत्रालय के साथ-साथ देश की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की साख का भी है।

इस प्रकरण के सामने आना एक मायने में सही साबित हुआ हे। इस प्रकरण से न जाने कितने ज्वलंत प्रश्न खुलकर सामने आ गए। पहला सवाल तो यही हे कि पूजा खेडकर को ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जब उनकी खुद की संपत्ति 17 करोड़ रुपए दर्ज है। उनके पिता भी एक पूर्व अधिकारी होने के साथ-साथ राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 40 करोड़ रुपए और आय 43 लाख रुपए वार्षिक दिखाई गई है। यह ठीक है कि पूजा ओबीसी समुदाय से आती हैं, लेकिन आठ लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले तो क्रीमीलेयर के दायरे में आते हैं। ऐसे लोग आरक्षण के हकदार नहीं होते।

इससे स्पष्ट हो जाता हे कि उन्हें ओबीसी प्रमाण पत्र गलत तरीके से दिया गया। इसके अलावा उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा ओबीसी कोटे के साथ-साथ दिव्यांग उम्मीदवार के रूप में दी है। ऐसे किसी प्रमाणपत्र के मामले में सत्यापन के लिए विशेष चिकित्सकीय परीक्षा होती है, परन्तु यूपीएससी द्वारा कई बार बुलाने पर भी वह इसके लिए नहीं गईं। हर एक बार एक नया बहाना बनाती रहीं, फिर उन्होंने खुद को दिव्यांग साबित करने के लिए एक निजी क्लीनिक से प्रमाण पत्र बनवाकर पेश कर दिया। यह मामला यूपीएससी की तरफ से कोर्ट में भी गया, लेकिन इसके बावजूद निजी क्लीनिक वाला उनका प्रमाणपत्र मान्य हो गया। आखिर कैसे स्वीकार किया गया? सवाल यह है कि यह किसके दबाव में किया गया?ओबीसी और दिव्यांगता के वर्ग में उनकी रैंक 841 थी। यानी कि उनके उऊपर अन्य मेधावी और सक्षम उम्मीदवार थे जिनकी कीमत पर उन्हें जगह मिली। इस प्रकार यह ओबीसी वर्ग के दूसरे छात्रों और दिव्यांगों की हकमारी का मामला भी है। निश्चित रूप से यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए ओबीसी के पैमाने से लेकर उन सभी मानकों की भी अनदेखी है, जिनका उल्लंघन करते हुए वह आईएएस बन गईं। ऐसे लोग मेरिट की कीमत पर लगातार जगह बना रहे हैं।

इस प्रकरण में एक बात साफतौर पर नजर आती है कि बिना राजनीतिक और प्रशासनिक सांठगांठ के पूजा खेडकर यहां तक नहीं पहुंच सकती थीं। आइएएस बनने के लोभ में वह वक्त से पहले भटक गईं और उन सुविधाओं की मांग करने लगीं, जो प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए ज्यादातर अफसर करते हैं। आखिर उनके जैसे अधिकारी जनता की सेवा कैसे करेंगे? वह ऐसी अकेली अधिकारी नहीं हैं। उनके पहले इस सूची में कई नाम दर्ज हैं, जिनपर भ्रष्टाचार के तमाम मामले दर्ज हैं। चाहे अभी जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल हों या मध्य प्रदेश के आईएएस दंपती। दरअसल नौकरशाही का कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं हैं। अगर हाल का उदाहरण लें तो तीन वर्ष पहले जिस आईपीएस अधिकारी ने यूपीएससी की एथिक्स यानी नैतिकता के प्रश्नपत्र में सबसे ज्यादा नंबर पाए थे, उसके अगले वर्ष की परीक्षा में उसे नकल करते पकड़ा गया। इससे स्पष्ट होता है कि भारत जैसे विशाल देश को एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था देने वाले इस स्टील फ्रेम में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है।

प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण ने देश की प्रशासनिक सेवा की कई संस्थाओं के कारनामों को एक साथ उजागर कर दिया है। पूजा खेडकर अभी लालबहादुर शास्त्री अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं उनकी यह ट्रेनिंग अगले साल जुलाई में पूरी होगी। इस दौरान उन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पुणे भेजा गया। वहां जाते ही उन्होंने सभी नियम-कायदे और नैतिकता को ताक पर रख ऐसे-ऐसे काम किए, जो देश की पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए कलंक कहे जा सकते हैं। उन्होंने वहां जाते ही लाल बत्ती लगी सरकारी गाड़ी, एक अलग ऑफिस घर और चपरासी इत्यादि की मांग की। यहां तक कि अपनी निजी ऑडी गाड़ी पर खुद ही अवैध रूप से लाल बत्ती भी लगवा लीं, जबकि उस गाड़ी के खिलाफ यातयात नियमों के उल्लंघन में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं और जुर्माना तक बकाया है। बीते दिनों उसे जब्त कर लिया गया। आईएएस अधिकारी बनने के बाद उन पर ऐसा नशा छाया कि पुणे में तैनात एक अन्य अफसर के कार्यालय में जबरन उनका नम हटाकर अपनी नेम प्लेट लगा दीं।

एक नई बहस को छेड़ने की तैयारी

भगवा ओढने वाले बाबा रामदेव को तो सबने अम्बानी के बेटे के साथ नाचते देखा। रामदेव शंकराचार्य नहीं हैं, लेकिन आचार्य तो है। उनका अचरण भी लोक पर असर डालता है।

हमारे धर्म गुरु न पोप की तरह आचरण कर पाते हैं और न धर्म की स्थापना और उसके लोकव्यापीकरण के बारे में ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी बौद्धिकता ही उन्हें खाए जाती है। वे अपने बौद्धिक अहंकार से ठीक उसी तरह ग्रस्त हैं जैसे कि हमारे देश के तमाम नेता सत्ता मद के अहंकार से ग्रस्त हैं।

लक्ष्मी पुत्रों के आगे हाजिरी बजाने वाले हमारे शंकराचार्य सनातन धर्म का न प्रचार कर सकते हैं और न धर्म ध्वजाएं लेकर चलने के अधिकारी हैं। उनका आचरण पाखंड की परिधि में आता दिखाई दे रहा है। वे राजसी आचरण कर रहे हैं। एक शंकराचार्य ने तो अपने सन्मुख झुके प्रधानमत्री के गले में अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला ऐसे डाली जैसे कोई राजा अपने किसी प्रिय व्यक्ति को इनाम दे रहा हो। मोदी जी रामलला के विग्रह की स्थापना समारोह में इन्हीं शंकराचार्य के विरोध के सामने झुके नहीं थे। मोदी ने तब मुमकिन है कि इनकी अहमन्यता को आहत किया था और अम्बानी के घर इनके सामने झककर उनके घावों पर मरहम लगा दिया। संयोग देखिये कि अनंत और राधिका की शादी के दिन यानी 12 जुलाई शुक्रवार को हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में जबरदस्त बूस्ट दिखा। रिलायंस के शेयर 1 फीसदी से अधिक चढ़ गए। शेयरों में तेजी से मुकेश अंबानी की संपत्ति में बड़ी बढ़ोतरी हई। इसके पीछे नववध के चरण हैं या शंकराचार्यों की कृपा, कहना मुश्किल है। मुझे कभी-कभी लगता है कि हमारे शंकराचार्यों से बड़े और लोकप्रिय धर्मध्वजा वाहक हमारे प्रधानमंत्री हैं। कम से कम उनके पीछे अंधभक्तों की एक लम्बी-चौड़ी फौज तो है। शंकराचार्यों के पास तो कुछ नहीं है। वे तो नेताओं की तरह कलियुगी कुबेरों के पिछलग्गू बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रख्यात साहित्यकार शरद कोकस कहते हैं कि धर्म और पूँजी एक- दूसरे को बढ़ावा देते हैं। कुछ मित्र शंकराचारयों के समर्थन में भी हैं। शच्चिदानन्द सूक्तकार कहते हैं कि अम्बानी परिवार का शंकराचार्यों से पराना रिश्ता है।

अनिल खमपरिया कहते हैं कि पहले इंद्र और कुबेर तक आशीर्वाद लेने मुनियों के आश्रम में जाते थे आज तो आश्रम ही कुबेरों के यहां अ गए हैं। कुछ को सीता स्वयंबर याद आ गया। उनका कहना है कि राम की बारात में तो कितने ऋषि-मुनि बाराती बन गए थे? कुल मिलाकर मैंने बहस छेड़ी है, औरों ने भी शायद छेड़ी हो, न छेड़ी हो तो भी कोई बात नहीं है। आप मुझे प्रतिसाद में मेरी पीठ भी थपथपा सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं।

दुनिया में ईसाईयों और बौद्धों के पास एक-एक धर्म गुरु पोप और दलाई लामा हैं लेकिन हम सनातनियों के पास एक के बजाय चार-चार धर्मगुरु हैं। लेकिन इन धर्मगुरुओं ने देश और दुनिया के शीर्ष धनकुबेर मुकेश अम्बानी के बेटे अनंत के विवाह आशीर्वाद समारोह में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी भूमिका पर खुद ही प्रश्नचिन्ह लगा लिए हैं। हमारे यहां परम्परा है कि हम सनातनी अपने धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेने उनके मठों में जाते हैं, लेकिन हमारे चार में से तीन शंकराचार्यों ने अपने मठों को ही अम्बानी के यहां ले जाकर एक अभिनव प्रयोग किया है। इस सुकृत्य के लिए इन शंकराचार्यों को अम्बानी परिवार की और से कितनी विदाई दक्षिणा मिली, कोई नहीं जानता। जान भी नहीं सकता, क्योंकि ये जानने के लिए हम या आप सूचना के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे एक सुधि मित्र साकेत साह कहते हैं कि विष्णुधर्म सूत्र (63 /26) कहता है कि सन्यासी को विवाह में नहीं जाना चाहिए इससे वह मोह-विछोह से पीड़ित हो सकता है। दक्ष स्मृति (7/34/28) कहती है कि सन्यासी को लोक व्यवहार नहीं करना चाहिए ऐसा करने पर वह धर्मच्युत हो जाता है और लोकवार्ता करने लगता है। मुझे विश्वास है कि हमारे शंकराचार्यों ने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा। मेरे मन में अपने धर्म गुरुओं के प्रति सीमित सम्मान है, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म गुरुओं की भूमिका में कमी की वजह से ही हमारा सनातन धर्म विश्वव्यापी नहीं बन पाया जबकि सनातन की कोख से ही जन्म बौद्ध धर्म कहाँ से कहाँ पहुँच गया।

इसाई और इस्लाम धर्म का विस्तार भी विश्वव्यापी है। हमारे धर्म गुरु न पोप की तरह आचरण कर पाते हैं और न धर्म की स्थापना और उसके लोकव्यापीकरण के बारे में ज्यादा मेहनत करते हैं। उनकी बौद्धिक्ता ही उन्हें खाए जाती है। वे अपने बौद्धिक अहंकार से ठीक उसी तरह ग्रस्त हैं जैसे कि हमारे श के तमाम नेता सत्ता मद के अहंकार से ग्रस्त हैं। शंकराचयों से तो डॉ मोहन भागवत भी अहंकार छोड़ने के लिए नहीं कह सकते। देश के शंकराचार्य अम्बानी के यहां हाजिरी लगाने से पहले अयोध्या में राम मदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण -प्रतिष्ठ समारोह के समय भी चर्चा में आए थे। हमारे शंकराचार्यों ने प्राण-प्रतिष्ठा समारोह को शास्त्रोक्त न मानते हुए उस समारोह का अघोषित बहिष्कार किया था।

शंकराचार्यों के प्रति हमारे सनातनियों में पोप जैसी प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि वे यदाकदा अपनी मयार्दाओं के बाहर जाकर आचरण कर दिखाते हैं। मेरे मन में शंकराचार्यों की बौद्धिकता का आतंक हमेशा रहता है। बहुत कम ऐसे शंकराचार्य हुए हैं जो सहज सम्मानित हुए है। मुझे एक बार काँची कामकोटि के शंकराचार्य की पत्रकार वार्ता से सिर्फ इसलिए बाहर जाना पड़ा था क्योंकि मैंने उनसे एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया था जो अनपेक्षित था। उनका आचरण ठीक वैसा ही था. जैसा आज के भाग्यविधाताओं का होता है। बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इकलौते ऐसे शंकराचार्य थे जो प्रश्नों से भागते नहीं थे, हालाँकि उनके ऊपर भी कांग्रेसी होने का आरोप लगाया जाता रहा, लेकिन वे उत्तेजित नहीं होते थे। बहरहाल बात चल रही है कि हमारे शंकराचार्यों को मुकेश अम्बानी के बेटे के विवाह समारोह में आशीर्वाद देने जाना चाहिए था या नहीं? उनका जाना धर्मसम्मत था या नहीं? इन प्रश्नों का उत्तर कोई दे या न दे किन्तु एक बात जाहिर हो गयी कि शंकराचार्यों के अम्बानी के यहां जाने से लोकधारणा ये बन गई है कि वे भी राजनेताओं की तरह लक्ष्मी के आगे ठीक वैसा ही नर्तन कर रहें हैं, जैसे कि दूसरे लोग। भगवा ओढने वाले बाबा रामदेव को तो सबने अम्बानी के बेटे के साथ नाचते देखा। रामदेव शंकराचार्य नहीं हैं, लेकिन आचार्य तो है। उनका अचरण भी लोक पर असर डालता है। हालाँकि वे अब खुद कुबेर हैं। अम्बानी के बेटे के विवाह समारोह में देश के प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम नेता, अभिनेता, दुनिया के कुवेर जाति के लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी उपस्थिति से कोई चौंका नहीं। क्योंकि उन्हें तो अम्बानी के यहां होना ही चाहिए था। लोगों को चौंकाया तो शंकराचार्यों की उपस्थिति ने। ये शंकराचार्य अपने दल-बल और सिंहासन के साथ अम्बानी के दरबार में हाज़िर थे। ये शंकराचार्य किसी आम आदमी के यहां विवाह समारोह का निमंत्रण मिलने पर वहां नहीं जा सकते, क्योंकि आम आदमी इन शंकराचार्यों के नाज-नखरे नहीं उठा सकता। ये शंकराचार्य हाथरस के हादसे में मारे गए लोगों के बीच नहीं जा सकते, मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि इन्हें इनका धर्म रोकता है। एक गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद हैं जो शंकराचार्यों के आाचरण की रक्षा कर सके। हालाकि वे भी मणिपुर या हाथरस नहीं गए। वे शायद जानते हैं कि ये काम नेताओं का है शंकराचार्य का नहीं।

लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की उठापटक चालू

अगला
कुछ महीनो में प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पांच में से भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन यदि भाजपा इन पांच सीटों को फिर से हार जाती है तो मुख्यमंत्री की नकारात्मक छवी बनेगी। इसलिए सरकार के समक्ष सभी पांच विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीतना एक मजबूत चुनौती बन गई है।

डॉ. किरोडी लाल मीणा मंत्रिमंडल के गठन के वक्त से ही नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन के वक्त उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुरूप महत्व नहीं मिला था। जिसके चलते वह अंदरखाने से नाराज चल रहे थे। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। डॉ. किरोडी लाल मीणा दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके उपरांत भी उन्होंने अपना मंत्री पद से इस्तीफा वापस नहीं लिया है। कहने को तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा पार्टी से नाराज नहीं है और वह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। मगर हकीकत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बजट सत्र में भी विधानसभा नहीं आकर डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी नाराजगी खुलकर जता दी है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने उपेक्षा से पहले से ही दुखी है। गाहे बेगाहे अपनी नाराजगी जाहिर करती रहती है। विधानसभा में भी वसुंधरा समर्थक विधायक सरकार को जमकर घेर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद वसुंधरा राजे को पूरी आशा थी कि उन्हें तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मगर जिस प्रकार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जेब से पर्ची निकाल कर वसुंधरा राजे से नए मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा करवाई। उससे वसुंधरा राजे की आम जनता में काफी फजीयत हुई थी। जिसे वसुंधरा अभी तक भूल नहीं पाई है।

लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 11 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार से जहां केंद्र में भाजपा कमजोर हुई है वही राजस्थान में तो भाजपा सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य सभी अग्रिम पंक्ति के नेताओं की जमकर किरकिरी हुई है। केंद्र सरकार में तीसरी बार मंत्री बने अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर लोक सभा सीट से महज 55711 वोटो के अंतर से जीत सके हैं। जबकि 2019 में वह 264081 व 2014 के चुनाव में 308079 वोटो के अंतर से चुनाव जीते थे। इस तरह देखे तो इस बार अर्जुन राम मेघवाल ने बहुत ही मुश्किल से चुनाव जीता है। जबकि उनके पड़ोस की श्रीगंगानगर, चुरु, झुंझनू, सीकर सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की हार हुई है।

लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान भाजपा में जमकर उठा पटक मची हुई है जो भविष्य में आने वाले तूफान के संकेत दे रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री डा. किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने सरकारी गाड़ी व अन्य सरकारी सुविधाएं भी लौटा दी है। यहां तक की डा. किरोड़ी लाल मीणा बजट सत्र में भी विधानसभा में नहीं आने की घोषणा कर चुके हैं। डा. किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के कद्दावर नेता हैं और राजस्थान में संघर्ष के प्रतीक रहे हैं। सरकार में हो या विपक्ष में वह अपनी बात पूरी मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं। तीसरी बार केंद्र सरकार में मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस के अनजान से प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा को 115677 वोटो से हराया है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को 274440 वोटो से व 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की कैबिनेट मंत्री चंद्रेश कुमारी कटोच को 303464 वोटो से चुनाव हराया था। इस बार के चुनाव में गजेंद्र सिंह का प्रभाव भी कम हुआ है। गजेंद्र सिंह के पड़ोस की बाड़मेर-जैसलमेर, नागौर, सीट पर भाजपा चुनाव हार गई है। जबकि पिछली बार यह सभी सीट भाजपा के पास थी। गजेंद्र सिंह शेखावत का शेरगढ़ विधायक बाबूसिंह राठौड़ से चुनाव पूर्व हुआ विवाद भी खास सुर्खियों में रहा था। बाड़मेर-जैसलमेर सीट पर तो भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर रहें थे। उन्हें मात्र 16.99 प्रतिशत यानि 286833 वोट ही मिल पाए थे। जबकि 2019 का चुनाव कैलाश चौधरी ने 323808 वोटो से जीता था। तब उन्हें 846526 वोट मिले थे।

लोकसभा चुनाव में चूरू सीट पर भाजपा सांसद राहुल कस्वां का टिकट काटे जाने से जाटों में भाजपा के प्रति काफी नाराजगी व्याप्त हो गई थी। जिसका खामियाजा उन्हें जाट बहुल अधिकांश सीटों पर हार कर चुकाना पड़ा था। पिछली बार भाजपा के पांच सांसद जाट वर्ग से थे। जबकि अबकी बार अजमेर से भागीरथ चौधरी जीत पाए हैं। लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने पुत्र के झालावाड़ संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित रही थी। उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में तो शामिल किया गया था। मगर चुनाव प्रचार के लिए कहीं नहीं भेजा गया। सीकर से दो बार भाजपा सांसद रहकर पिछला चुनाव हार चुके स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने खुलकर कहा है कि यदि वसुंधरा राजे से चुनाव प्रचार करवाया जाता तो नतीजे हटकर मिल सकते थे।

झुंझुनू से भाजपा टिकट पर चुनाव में पराजित हुए शुभकरण चौधरी ने अपनी हार का कारण अग्निवीर योजना को बताया था। भाजपा के बहुत से नेताओं का मानना है कि राजस्थान से सेना में सर्वाधिक नवयुवक भर्ती होते हैं। अग्निवीर योजना आने के बाद राजस्थान के युवाओं में खासी नाराजगी व्याप्त हो रही है। कांग्रेस ने वायदा किया था कि उनकी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना बंद कर देगी। इससे बड़ी संख्या में नवयुवकों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं भी सभी 25 संसदीय सीटों पर प्रचार के लिए नहीं पहुंच सक थे। मुख्यमंत्री स्वयं चुनाव के दौरान व्यवस्थित ढंग से चुनाव प्रचार नहीं कर सके। इसी के चलते अपने गृह जिले भरतपुर की लोकसभा सीट भी हार गए। कोटा जैसी भाजपा की मजबूत सीट पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बार महज 41974 वोटो के अंतर से ही जीते हैं। जबकि पहले के चुनाव में उनकी जीत का अंतर लाखों वोटो में होता रहा था।

राजस्थान में भाजपा की सरकार बने सात महीने से अधिक का समय हो चुका है। मगर अभी भी सरकार पर मंत्रियों की पकड़ नहीं बन पाई है। अधिकारी वर्ग मंत्रियों की बातों को अधिक तवज्जो नहीं देते हैं। जिसके चलते मंत्रियों द्वारा आम जनता मे की गई घोषणाएं पूरी नहीं होने से उनकी स्थिति हास्याद पद बन जाती है। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष एक ही जाती के हैं। विभिन्न निगम, बोर्ड, आयोग, मण्डलों में भी अभी तक या तो पीटे हुए मोहरों को या अधिकारियों को ही नियुक्ति दी गई है। जमीन पर काम करने वाले कार्यकताओं को तवज्जो नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री के इर्द-गिर्द वही चौकड़ी रहती है जो उनके प्रदेश महामंत्री रहते उनके साथ रहती थी। इससे आम जनता में सरकार की छवि खराब हो रही है।

अगले कुछ महीनो में प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पांच में से भाजपा के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन यदि भाजपा इन पांच सीटों को फिर से हार जाती है तो मुख्यमंत्री की नकारात्मक छवी बनेगी। इसलिए सरकार के समक्ष सभी पांच विधानसभा सीटों के उपचुनाव में जीतना एक मजबूत चुनौती बन गई है।

भाजपा अपना अधिकतम पा चुकी

उत्तराखंड में कांग्रेस को लोकसभा की एक भी सीट हासिल नहीं हो पायी थी लेकिन उसने बद्रीनाथ और मंगलर की दोनों सीटों को इस उपचुनाव में जीत लिया है। बद्रीनाथ चार धामों में एक धाम है जो इसी सीट के तहत आता है। कांग्रेस के लिए यह महत्वपूर्ण सीट हो जाती है क्योंकि भाजपा अपने को धार्मिक पार्टी जैसा बताती आयी है। वहीं हिमाचल की तीन सीटों में से दो सीटें जो पहले निर्दलीयों के पास थीं और हिमाचल की कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के लिए उनके इस्तीफे कराये गए थे और उन्हें भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारा गया था, काग्रेस ने जीत ली हैं। एक सीट भाजपा के खाते में आयी है। हिमाचल की दी सीटों के कांग्रेस के खाते में आने से सुक्खू की सरकार बच गई है। जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार रहते भी काग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। वहीं पंजाब में एक सीट पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत गई और तमिलनाडु की सीट पर डीएमके को जीत मिली है। मध्यप्रदेश में एक साट पर उपचुनाव हुआ जो भाजपा के खाते में गई। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि भाजपा बहुत कमजोर हो गयी है या पूरी तौर पर हार गई है और विपक्ष बहुत मजबूत हो गया है। इस चुनाव में जनता का सन्देश यही है कि भाजपा से अब जनता का मोहभंग हो रहा है और उसे भाजपा की सरकार के वादे और काम एक छलावा लगने लगे हैं। वहीं इंडियारढबंधन के कांग्रेस और राजद के लिए भी संदेश साफ है कि इस पर इतराने के बजाय बहुत मेहनत करनी होगी।

लोकसभा चुनाव के लगभग डेढ़ माह बाद सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव परिणाम में इंडिया गठबंधन के दलों ने दबदबे को बनाये रखने का काम किया है। 10 जुलाई को सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इनमें पश्चिम बंगाल की चार, हिमाचल प्रदेश की तीन, उत्तराखंड की दो और बिहार, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश और पंजाब की क्रमशः एक-एक सीट शामिल है। जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने का काम किया था कि भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। आज यदि भाजपा की केन्द्र में सरकार बनी है तो उसका सारा दारोमदार राजग के दो घटक नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड और आन्ध्र प्रदेश की चन्द्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलगूदेशम पार्टी को है। जिसकी वजह से नरेन्द्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके हैं। इसका यह अर्थ कदापि नहीं, कि इंडिया गठबंधन को भाजपा से अधिक सीटें मिल गई। लेकिन यदि यह दो घटक भाजपा के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन में न होते तो अन्य घटक भी किसी भी ओर जा सकते थे। इस प्रकार इन दो घटकों की बैसाखी पर नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल टिका हुआ है। जब तक वह अन्य दलों में तोड़-फोड़ करके अपने में शामिल नहीं कर लेते हैं। सात राज्यों में हुए उपचुनाव की 13 सीटों में भाजपा को सिर्फ दो सीटें हासिल हुई हैं। सबसे अधिक मजबूती तो पश्चिम बंगाल में ममता बनजी की तृणमूल कांग्रेस ने दिखाई है जिसने लोकसभा में पिछले चुनाव परिणाम की अपेक्षा ज्यादा सीटें लेकर आयी जबकि भाजपा ने इतना ताम-झाम फैला रखा था कि बाहर से यही लग रहा था कि भाजपा की सीटें पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी लेकिन 'दीदी' की आक्रामकता में भाजपा को जीतने नहीं दिया। उपचुनाव की चार सीटों की स्थिति भी यही रही कि भाजपा की तीनों सीटों पर तृणमूल ने कब्जा कर लिया। ममता बनर्जी ने कह भी दिया कि पूरे देश में माहौल भाजपा के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इंडिया गठबंधन को इस उपचुनाव में 51 फीसदी मत मिले जबकि राजग को सिर्फ46 फीसदी मत ही हासिल हुए। वहीं बिहार की रूपौली सीट के उपचुनाव में भाजपा- जदयू गठबंधन को नुकसान हुआ है और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। जनता दल यू की कई बार विधायक रही बीमा भारती जो राजद में थी, चुनाव हार गई हैं। वह पहले लोकसभा चुनाव भी लड़ी थीं जो पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी हार गई थीं। यह झटका सिर्फराज्य में सत्तारूढ़ जदयू भाजपा गठबंधन को लगा है बल्कि यह सन्देश कहीं अन्दर तक इंडिया गठबंधन के घटक राजद को गया है कि वह अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाया।

उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर उपचुनाव होना है जिसमें असली लड़ाई सामने आयेगी। बैकफूट पर खड़ी बसपा जो उपचुनाव लड़ती ही नहीं थी इस बार सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएगी वहीं आजाद पार्टी जो बसपा के नक्शे कदम पर बसपा को किनारे लगाते हुए अपना प्रभाव जमाना चाहती है, अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गई है। इसके अध्यक्ष चन्द्रशेखर नगीना सीट से निर्दलीय सांसद निर्वाचित हुए हैं।

संसद में उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि वे न तो सत्तापक्ष के साथ हैं और न हीं विपक्ष के साथ वह दलितों वचितों के हित में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर सात राज्यों में 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में जनता ने राजग और भाजपा को यह संदेश दे दिया है कि देश की हवा बंदल रही है। भाजपा अपना अधिकतम पा चुकी है।

ईरान खुद पेजेश्कियान की विजय से हैरान

भारत में हिजाब को लेकर एक बड़ा झंझावात चल रहा है। भारतीय मुस्लिम पुरुष समुदाय जहां हिजाब के पक्ष में खड़ा है वहीं मुस्लिम महिलाएं हिजाब, बुर्के व नकाब आदि को अपनी स्वतंत्रता व शिक्षा में बाधा मानती हैं। अनेक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि वस्तुतः भारतीय मुस्लिम स्त्री समुदाय की अशिक्षा का एक बड़ा कारण बुर्का, हिजाब व नकाब ही है। ईरान में राष्ट्रपति रईसी की हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात चुनाव कठिन लगने लगे थे। किंतु, अब जब चुनाव हो गये हैं तो ईरान एक नये स्वरूप में व नये मार्ग पर दिखाई दे रहा है। जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी जैसी संघर्षशील महिला भी इन चुनावों के प्रति उदासीन व निराश थीं व उन्हें लगता था कि इन चुनावों का बहिष्कार ही एक मात्र उपाय है। न जाने क्या हुआ कि इस चुनाव में ईरान के सुधारवादियों, विशेषतः पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी को नई आशा की किरण दिखाई दी। खातमी ने निष्क्रियता छोड़ी व मसूद पेजेश्कियान के समर्थन में कूद पड़े। चुनाव के प्रथम चरण में चुनाव चाहने वालों व बहिष्कार करने वालों के मध्य संघर्ष हुआ फलस्वरूप मतदान का प्रतिशत चालीस से भी नीचे चला गया था। दूसरे चरण में कट्टरपंथी जलीली व पेजेश्कियान के मध्य सीधे चुनाव में एकेडेमिक छवि वाले जरीफ ने पेजेश्कियान के लिए सघन अभियान चलाया। जरीफ व पेजेश्कियान ने घोषणा की कि, उनकी विदेश नीति न तो पश्चिम विरोधी है और न ही पूरब विरोधी। इन दोनों ने ईसी की रूस और चीन से लगाव की नीति की आलोचना की। ईरान के आर्थिक संकट को हाल करने हेतु भी उन्होंने अपना रोडमैप प्रस्तुत किया। परमाणु विषय पर व्यवस्थित बात करने व ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने हेतु भी वे संकल्पित दिखाई पड़े। यद्दपि ईरान की आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण निर्णय प्रक्रिया पर पूर्ण अधिकार अब भी सर्वोच्च धार्मिक नेता खामनेई का ही रहेगा। खामनेई के कट्टरपंथी दृष्टिकोण को चुनाव के बाद की कुर्द्स फोर्स से संबंधित से बातों से समझा जा सकता है जो उन्होंने कही है। ईरान की नीतियों पर कुद्स का प्रभाव सदैव रहता है। कुद्स फोर्स आईआरजीसी की बाहरी इकाई है व राष्ट्रपति के पास इस पर सीधे नियंत्रण का अधिकार नहीं होता है। केवल ईरान के सर्वोच्च नेता ही यह निर्णय करते हैं कि कुद्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खामनेई ने समूची चुनावी प्रक्रिया के मध्य इस बात को दोहराते रहें हैं कि कुद्स फोर्स जो कर रही है वो देश की सुरक्षा नीतियों की दृष्टि से अनिवार्य है। इजराइल-फि लिस्तीन संघर्ष में मध्य-पूर्व में ईरान ही हमास का प्रमुख समर्थक रहा है। पश्चिम विरोधी नीतियों के कारण भी इनकी स्थिति असहज होती रही है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने तो सीधे इसराइल पर आक्रमण करके अभूतपूर्व स्थिति निर्मित कर दी थी। इससे दोनों देश आमने-सामने आ गए थे। ईरान में महिलाओं पर मॉरल पोलिसिंग के पक्ष में सुदृढ़ कट्टरपंथी कानून बने हुए हैं। पेजेश्कियान जो महिलाओं की नैतिक पोलिसिंग का विरोध करते हैं और पश्चिम के साथ टकराव की बजाय जुड़ाव का आग्रह रखते हैं। अब आर्थिक संकटों और सामाजिक उलझनों से त्रस्त ईरान स्वयं पेजेश्कियान की इस विजय से आश्चर्यचकित है। अब तक ईरान की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तथाकथित 'प्रिंसिपलिस्टों' (रूढ़िवादियों) के नियंत्रण में थी। ये ईरान में किसी भी प्रकार के सुधारों के विरोधी थे। ईरान में चुनावों के मध्य ईरान सरकार में कभी मंत्री रहे सुधारवादी पेजेश्कियान को जब गार्डियन काउंसिल ने चुनाव में प्रत्याशी मान लिया तब ईरान के सुधारवादी गठबंधन ने अपना समर्थन उनके पक्ष में दे दिया।

घूँघट की बगावत

21 जुलाई 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

6

काशी में पहुंचने लगे कांवड़िए, हर-हर महादेव के उद्घोष संग गंगा में लगाई डुबकी; सुरक्षा रही दुरुस्त

काशी नगरी में कांवड़ियों के आने का सिलसिल शनिवार से शुरू हो गया। जौनपुर, चंदौली से आए शिवभक्तों ने बाबा के दर्शन से पहले गंगा में डुबकी लगाई। हर-हर महादेव के उद्घोष के साथ उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका।

डीएम-एसएसपी ने कांवड़ मार्ग और धार्मिक स्थलों का किया मुआयना

मेरठ (जीकेबी)। कांवड़ यात्रा सुरक्षा मद्देनजर सोमवार को सावन के पहले दिन डीएम और एसएसपी में कांवड़ मार्ग और धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और कांवड़ मार्ग पर लगने वाले शिविरों की जानकारी ली।

डीएम दीपक मीणा के निर्देशन में लगातार व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। इसी क्रम में सोमवार को दीपक मीणा व एसएसपी विपिन ताडा ने बेगमपुल, औघड़नाथ मंदिर, रोहटा रोड, गंगनहर पटरी सलावा व सिवाया टोल प्लाजा कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए कांवड़ मार्ग पर शेष व्यवस्था को पूर्ण कराया जाए। कांवड़ मार्ग पर उन्होंने कांवड़ियों से वार्ता की व व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर सीडीओ नूपुर गोयल, जिला पंचायत राज अधिकारी रेनू श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव : छह अगस्त को मतदान, मतगणना 8 को

पडरौना, कुशीनगर(जीकेबी)। पडरौना जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए मंगलवार को समय सारिणी घोषित की। समय सारिणी के अनुसार आकस्मिक रूप से रिक्त पड़े ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए छह अगस्त को मतदान और आठ अगस्त को मतगणना कराई जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्र ने बताया कि ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक रखी गई है। 23 जुलाई को सुबह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्देशन पत्रों की जांच होगी। 24 जुलाई की सुबह दस बजे से शाम तीन बजे तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। इसके बाद उसी दिन शाम तीन बजे के बाद कार्य समाप्ति तक प्रतीक चिह्नों का आवंटन होगा। इसके बाद छह अगस्त को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा और आठ अगस्त को सुबह आठ बजे से कार्य की समाप्ति तक मतगणना कर चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।

इन गांवों में होना है प्रधान का चुनाव

दुदही ब्लॉक के अहिरौली गांव में प्रधान पद का चुनाव होगा। इस गांव को आरक्षण वर्ग अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के दरबहागंगा छपरा गांव में प्रधान पद के लिए आरक्षण वर्ग अनारक्षित, फाजिलनगर ब्लॉक के कस्तूरबा गांव के में प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति, विशुनपुरा ब्लॉक के बड़हरागंज गांव में प्रधान पद के लिए महिला वर्ग और सेवरही ब्लॉक के मुस्तकीम गांव में प्रधान पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य

कप्तानगंज ब्लॉक के सदस्य संख्या आठ, ब्लॉक कसया सदस्य संख्या एक, ब्लॉक खड्डा के सदस्य संख्या 15, ब्लॉक तमकुहीराज के सदस्य संख्या 34, ब्लॉक दुदही सदस्य संख्या 16, ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया के सदस्य संख्या 40, ब्लॉक पडरौना के सदस्य संख्या 41, ब्लॉक फाजिलनगर के सदस्य संख्या 21, ब्लॉक मोतीचक के सदस्य संख्या नौ, ब्लॉक रामकोला के सदस्य संख्या 18, ब्लॉक विशुनपुरा के सदस्य संख्या सात, ब्लॉक सुकरौली के सदस्य संख्या चार, ब्लॉक सेवरही के सदस्य संख्या 21, ब्लॉक हाटा के सदस्य संख्या चार रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य हैं। यहां उपचुनाव होना है।

रिक्त बीडीसी सदस्य पदों का विवरण

कप्तानगंज के क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए पकड़ी, तमकुहीराज के महुअवा बुजुर्ग व बसडिला महंथ, दुदही ब्लॉक के कुबेरा भुआल पट्टी व सरिसवा, ब्लॉक नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के सिंगहा, ब्लॉक पडरौना क्षेत्र के भिसवालाला नंबर दो व सखवनिया बुजुर्ग, ब्लॉक विशुनपुरा के जटहां बाजार और सुकरौली के पड़री नंबर चार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का उपचुनाव होना है।

सेवायोजन में पंजीकरण कराने में रुचि नहीं दिखा रहे युवा

महराजगंज (जीकेबी)। सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने में युवाओं की रुचि कम होती जा रही है। पंजीकरण के लिए सेवायोजन विभाग रोजगार मेला के अलावा युवाओं को तरह तरह से जागरुक कर रहा है।

वर्ष 2020 में सेवा योजन पोर्टल पर 2351 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, वर्ष 2021 में 3522 युवाओं ने पंजीकरण कराया, 2022 में 2629 युवाओं ने पंजीकरण कराया जबकि 2024 का आधा साल बीतने को है, लेकिन अभी तक मात्र 1144 युवाओं ने ही रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है।

साल दर साल बीत रहा है लेकिन रोजगार पोर्टल पर युवाओं के पंजीकरण में विशेष वृद्धि नहीं दिख रही है। किसी साल हजार युवाओं की संख्या बढ़ रही है तो दूसरे साल उससे भी कम हो जा रही है। युवाओं का पंजीकरण बढ़ाने और रोजगार दिलाने के लिए सेवायोजन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। रोजगार मेला भी इसका एक माध्यम है।

वर्ष 2020 में रोजगार पोर्टल पर 2351 युवा, 2021 में 3522 युवा, 2022 में फिर पंजीकरण गिरा और 2629 युवाओं ने ही पंजीकरण कराया, 2023 में 4626 युवाओं ने पंजीकरण कराया जबकि 2024 का आधा साल बीतने को है रोजगार पोर्टल पर 1144 युवाओं ने ही पंजीकरण कराया है।

सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है। सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से सरकारी, प्रइवेट भर्तिया की जा रही हैं। इसके अलावा रोजगार मेला का भी आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेला में स्थानीय स्तर और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से कंपनियां पहुंचकर युवाओं का चयन रोजगार के लिए कर रही है। वर्ष 2023-24 में सेवायोजन कार्यालय के बैनर तले जनपद में 22 रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जिसमें 9075 युवाओं ने प्रतिभाग किया। रोजगार मेला के माध्यम से 5116 युवाओं को रोजगार मिला। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक जनपद में चार रोजगार मेला का आयोजन किया गया। जिसमें एक हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। रोजगार के इच्छुक युवाओं को रोजगार के लिए सेवायोजन पोर्टल पर जरूर पंजीकरण कराना चाहिए।

▶ जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी पर शिकंजा कसना शुरू

कनमिसवा सीमा पर तस्करों ने एसएसबी जवान पर किया हमला, गाड़ी तोड़ी

(जीकेबी)

महराजगंज/निचलौल। नेपाल सीमा पर स्थित कनमिसवा गांव में बृहस्पतिवार भोर में तस्करों ने एसएसबी जवानों पर हमला कर दिया। इस हमले में एसएसबी का एक इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। एसएसबी का गश्ती वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही एक इंस्पेक्टर भी जख्मी हो गया है। घायल इंस्पेक्टर की तहरीर पर 16 नामजद समेत 41 के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं।

माना जा रहा है, की जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इससे आक्रोशित होकर तस्कर जवानों की कभी वाहन चोरी कर तो कभी जानलेवा हमला कर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से सरहद की सुरक्षा में लगे जवानों के साथ ही सरहद से सटे गांव के लोग भी डरे हुए है। तस्करों के हमले से बॉर्डर पर पूरे दिन सरगर्मी देखने को मिली। पुलिस और एसएसबी के उच्चाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे मौके का जायजा लेते रहे।

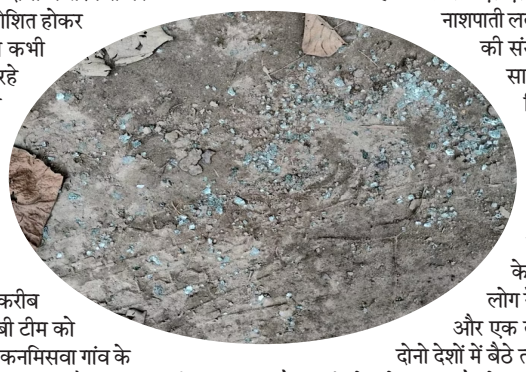

जानकारी के मुताबिक, बृहस्पतिवार भोर में करीब सवा तीन बजे झुलनीपुर बीओपी की एसएसबी टीम को सूचना मिली की पिलर संख्या 499/4 से सटे कनमिसवा गांव के पास पिकअप से चाइनीज नाशपाती भारत लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसएसबी टीम गश्त करने वाली सरकारी वाहन से मौके पर पहुंच गई। टीम ने देखा की चाइनीज नाशपाती लदे दो पिकअप नो मेंस लैंड के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। एसएसबी को देखते ही दोनों पिकअप चालक वाहन छोड़ भाग निकले। इसकी सूचना सीमा शुल्क अधिकारियों को देकर जवान दोनों वाहनों का निरीक्षण करने लगे। इसी बीच अचानक भारी संख्या में तस्कर गोलबंद होकर लाठी डंडों के साथ आ धमके। एसएसबी के जवान कुछ समझ पाते इससे पहले तस्करों ने उनपर हमला कर दिया। इस दौरान इंस्पेक्टर (जीडी) मुकेश कुमार के बाएं हाथ पर चोट लगी है। किसी तरह एसएसबी के जवान वहां से बच कर निकले। इसके बाद तस्करों ने एसएसबी के सरकारी वाहन पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हमले के बाद तस्कर अपने वाहन उठा ले गए।

थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार सिंह ने कहा की एसएसबी जवानों से मिली घटना की जानकारी के तत्काल बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच घटना का जायजा लिया गया। एसएसबी की सख्ती के कारण तस्करों ने गुस्से में जवानों पर हमला किया है। एसएसबी के निरीक्षक मुकेश कुमार की तहरीर पर पुलिस ने संतोष यादव समेत 15 नामजद और 25 अज्ञात पर केस दर्ज कार्रवाई की जा रही है।

40 से 50 की संख्या में थे हमलावर

सूत्रों के मुताबिक, कनमिसवा बार्डर के रास्ते चाइनीज नाशपाती लेकर भारत की ओर आ रहे दोनों पिकअप चालक एसएसबी जवानों को देख भाग निकले। फिर इसकी जानकारी पिकअप चालकों ने नेपाल और भारत में बैठे तस्करों के मुख्य सरगनाओं को दी। तस्करी का वाहन रोकने की बात सुन तस्कर आक्रोशित हो उठे। फिर एसएसबी जवानों के चंगुल से पकड़े गए चाइनीज नाशपाती लदी दोनो पिकअप को छुड़ाने के लिए 40 से 50 की संख्या में तस्कर गोलबंद होकर लाठी डंडों के साथ मौके पर आ पहुंचे। तस्करों ने दुस्साहस दिखाते हुए जवानों और उनके वाहनों पर हमला कर पकड़ी गई दोनों पिकअप छुड़ा ले गए।

सरहद से लेकर शहरों तक सक्रिय हैं तस्कर

सूत्र बात रहें हैं की भारत-नेपाल का बार्डर खुला होने के कारण आसानी से तस्करी होती रहती है। भारत और नेपाल के गांवों को जोड़ने के लिए हर गांव में पगडंडी है। उसी से भारत के लोग नेपाल और नेपाल के लोग भारत आते रहते हैं और एक दूसरे के सुख-दुख के भागीदार बने रहते हैं। दोनो देशों में बैठे तस्कर इन्हीं पगडंडी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बार्डर से सटे भारत और नेपाल के हर गांव में तस्कर मौजूद हैं। यह तस्कर सरहद से लेकर निचलौल शहर तक काफी सक्रिय रहते है। फिर निचलौल शहर के आगे बड़े शहरों तक अवैध समानों को भेजने के लिए तस्कर दूसरे एजेंट पर निर्भर रहते है। सीमावर्ती गांवों से लेकर शहर तक तस्कर गोदाम बना रखे है।

घटना के बाद वायरल वीडियो बना चर्चा

एसएसबी जवानों पर हमला कर तस्करी की पकड़ी गई चाइनीज नाशपाती लदी दो पिकअप छुड़ाने के बाद 22 सेकेंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिसे लेकर लोग तस्करों के दुस्साहस की निंदा कर रहे हैं। वहीं पुलिस तथा सुरक्षा एजेंसियों पर सरहद की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़ा कर रहे हैं। वायरल वीडियो में रात के अंधेरे में तस्करी के सामान लदे दर्जनों वाहन एक साथ गुजर रहे हैं। इतना ही नहीं इस पर आडियो लगाया गया है, की राना का माल तो बड़ी शान से राना तक पहुंचेगा डीके, ले जाने की बात तो भूल जाओ, अगर गलती से तुमने उसे देख भी लिया, तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे, की तुम्हारी आने वाली नस्लों की नींद भी उस मौत से उड़ जाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जबरा फैन:

जिसने अपने सीने पर बनवाया उनका टैटू

जातिगत विभाजन : अन्नाद्रमुक के लिए रणनीतिक और राजनीतिक चुनौती

'लोकसभा चुनाव के मतदान का पैटर्न इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि अन्नाद्रमुक के मतदाता दूसरे दलों का रुख कर रहे हैं। एमजीआर और जयललिता के वफादार पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अन्ना द्रमुक के अलग-अलग गुटों के विलय के लिए संपर्क करने के उद्देश्य से एक शांति समिति बनाई है। पार्टी कार्यकर्ता द्रमुक से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व चाहते हैं, जो अन्नाद्रमुक का कट्टर विरोधी है। लेकिन सभी चारों गुट अलग-अलग समय पर द्रविड़ संस्कृति के समर्थन का एक ही राग अलापते हैं और प्रकारान्तर से एमके स्टालिन की मदद करते हैं।'

अन्ना द्रमुक का भविष्य क्या है? अगर बिना किसी पूर्वाग्रह के राजनीतिक नजरिये से विश्लेषण किया जाय तो अन्नाद्रमुक का भविष्य अंधकारमय है। सभी अलग-अलग गुटों द्वारा आपस में विलय नहीं किया गया, तो अन्नाद्रमुक में में और विभाजन हो सकता है। इस बार यह विभाजन खुले तौर पर द्रमुक या भाजपा के पक्ष में होगा।

दुर्भाग्य से अन्नाद्रमुक के विभाजन के दौर में कांग्रेस ने प्रयास किया था, लेकिन उसका द्रमुक के साथ इतना मजबूत गठबंधन है कि कांग्रेस ने एडापडी पलानीस्वामी से दूरी बना ली। इसलिए कांग्रेस अन्नाद्रमुक के विभाजन से अलग-थलग है। क्या अन्नाद्रमुक के विभाजन में नई दिल्ली का हाथ है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से है। जयललिता के निधनोपरान्त तुरन्त बाद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रणनीतिक प्रस्ताव दिया था, जिसे एडापडी पलानीस्वामी ने नहीं माना। यदि भाजपा के प्रस्ताव को लोकसभा चुनाव में मंजूर कर लिया गया होता, तो द्रमुक को राज्य में सभी सीटें नहीं मिलती और एडापडी के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक राजग सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होती। वर्ष 2026 का राज्य विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। अगर एडापडी पलानीस्वामी फिर से अड़े रहे, तो एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक के लिए 2026 का राज्य विधानसभा चुनाव जीतना आसान होगा। इससे डॉ. अंबुमणि रामदास के पीएमके, जीके वासन के तमिल मनीला कांग्रेस(टीएमसी), सीमन के एनटीके (नाम तमिल काच्ची) जैसे शेष आठ छोटे दलों में और भी अधिक अव्यवस्था होगी।

तमिलनाडु में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है। वर्ष 172 में एमजी रामचंद्रन द्वारा स्थापित पार्टी, जिसे बाद में शक्तिशाली नेत्री जयललिता ने कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाया। जयललिता के निधनोपरान्त वह तीन गुटों में विभाजित हो गई। जय ललिता के निधन के बाद एडापडी पलानीस्वामी ही वह नेता हैं, जिन्होंने चार वर्षों तक तमिलनाडु में शासन किया था। मजेदार बात यह है कि उन्होंने अन्नाद्रमुक के अधिकांश कार्यकर्ताओं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और विशेष रूप से दो पत्तियों वाले प्रसिद्ध चुनाव चिह्न को बरकरार रखा।

एडापडी पलानीस्वामी ने हाल ही में चेन्नई में जिलावार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें चुनावी हार पर उनके विचारों का श्रवण किया गया। वर्ष 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव के बाद जो लोग एडापडी पलानी स्वामी से अलग हो गए थे, वे अब अलग-अलग गुटों का विलय चाहते हैं। इनमें (तमिलनाडु के थेवर जाति के कद्दावर नेता ओ.पन्नीसेल्वम, उसी जाति समूह के नेता टीटीवी दिनाकरण, (जो एक राजनीतिक अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के प्रमुख हैं)और थेवर जाति की शशिकला) शामिल हैं। तमिलनाडु में 1967 से द्रविड़ पार्टियां विभाजित हैं और उनके आठ संगठन हैं। ये सभी हिंदुत्व और भाजपा के वर्चस्व का विरोध करते हैं। एमजीआर एवं जयललिता ही तमिलनाडु में नरम हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आए थे। इसी वजह से जयललिता ने राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का पुरजोर समर्थन किया था। राजनीति की यह भिन्न वैचारिक शैली, जो द्रविड़ विचारधारा के विरुद्ध है, दो शक्तिशाली जातियों गौंडर और थेवर के दो प्रमुख नेताओं एडापडी पलानीस्वामी और ओ. पन्नीसेल्वम की मदद कर रही है, लेकिन अन्नाद्रमुक के समर्थक और कार्यकर्ता एमके स्टालिन और द्रमुक के राजनीतिक रूप से उसी तरह लड़ना चाहते हैं, जिस तरह जयललिता लड़ती थीं।

जातिगत राजनीति से तंग आकर अधिकांश कार्यकर्ता अब अन्नाद्रमुक से पलायन कर रहे हैं। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव और आल ही में जुलाई में संपनन विक्रवंडी विधानसभा उपचुनाव के बाद यह पलायन अन्नाद्रमुक के लिए अस्तित्व के संकट की चुनौती के रूप में आया है। गौंडर खेमा भाजपा से बाहर चला गया है। लेकिन थेवर समूह भाजपा के साथ बना रहा। इसलिए अन्नाद्रमुक न केवल विचारधाराओं के आंतरिक संकट का सामना कर रही है, बल्कि जातिगत वर्चस्व का भी सामना कर रही है। हर कोइ एक-दूसरे पर जातिगत वर्चस्व का आरोप लगा रहा है।

तमिलनाडु में वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर एमजीआर के कुछ वफादारों की शांति समिति सफल नहीं होती है, तो कार्यकर्ताओं में और विभाजन का खतरा है, और एडापडी पलानीस्वामी खेमे से पांचवे विभाजन की आशंका है।

एडापडी खेमे कें भीतर से एसडीपीआई और एनटीके जैसी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की आवाजें सुनी जा रही हैं, जिसका नेतृत्व सीमन कर रहे हैं। सीमन गुट भी द्रविड़ विचारधारा से है। सीमन तमिल ईलम मुद्दे का कट्टर समर्थक हैं और खुद को लिट्टे नेता प्रभाकरण की तरह पेश करता है। क्या एडापडी पलानीस्वामी को सीमन के एनटीके के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? एडापडी पलानीस्वामी राज्य में ताकतवर गौंडर जाति से ताल्लुक रखते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एडापडी समूह को भारी झटका लगा, क्योंकि इसके कई उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। लगातार दस चुनावो में, चाहे वह नगर निगम का हो या विधानसभा का हो, लोकसभा का हो । एडापडी पलानीस्वामी एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सत्तारूढ द्रविण मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) से परास्त हो गए हैं। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक गौंडर और थेवर जातियों तक सिमट कर रह गई हैं। इसलिए कार्यकर्ता इन गुटों में विलय चाहते हैं। राज्य में अन्ना द्रमुक का जनाधार सिमट गया है। उसकी ज्यादा बड़ी जगह या तो सत्तारूढ द्रमुक या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा छीनी जा रही है।

व्यष्टि से समष्टि तक के एकाकार की यात्रा चातुर्मास

बड़े त्योहारों में केवल होली है जो इस चातुर्मास की अवधि से बाहर है। यदि कोई शुभ कार्य नहीं हो सकते तो बड़े-बड़े त्योहारों की श्रृंखला का प्रावधान इसी अवधि में क्यों किया गया है ?इस प्रश्न का उत्तर हमें इन आयोजनों में मिल जाता है। चातुर्मास में जो त्योहार होते हैं, और जिन आयोजन को या कार्यों को निषेध बताया गया है इन दोनों काविचार करें तो पाते हैं कि वर्जित किए गए सभी आयोजन भले दिखने में सामूहिक लगते हैं, उनका आयोजन समूह में होता हो पर वे सभी व्यक्तिगत हित के उत्सव हैं, व्यक्तिगत प्रभाव की स्थापना या प्रदर्शन के आयोजन हैं। उन आयोजनों में समाज या राष्ट्र में निहित नहीं है। लेकिन इन चार माह में जिन त्योहारों का प्रावधान किया गया हे वे सब व्यक्ति, परिवार, समाज,राष्ट्र और लोककल्याण के हैं। व्यक्तिगत हित या व्यक्तित्व के प्रभाव का प्रदर्शन एक बात है। जैसे- विवाह, नामकरण, यज्ञोपवीत नए घर का निर्माण इत्यादि कार्य केवल व्यक्ति या परिवात हित तक ही सीमित होतेहैं। इनमें व्यक्तिगत संतोष और सुख तो मिलता है लेकिन परिवार का आंतकिर उत्थान नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जिन त्योहारों के आयोजन होते हैं वे सब किसी निजीत्व के प्रदर्शन या प्रसन्नता के लिए नहीं अपितु व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के सशक्तिकरण या समष्टिकण के निर्मित हैं। उनका उद्देश्य व्यक्ति को तन से, मन से, बुद्धि से और विवेक के बल से समृद्ध बनाना है, परिवार को सशक्त बनाना हे, समाज को संगठित और उन्नत बनाना है और संपूर्ण राष्ट्र एकता के सूत्र में आबद्ध करना है त्योहारों के माध्यम से चातुर्मास की इस अवधि में व्यष्टि से समष्टि तक के एकाकार की यात्रा होती है।

भारतीय वाड्मय में कोई उत्सव, कोई त्योहार, अथवा कोई परंपरा यूं ही नहीं होती। उसके पीछे गहरा अनुसंधान होता है, व्यक्ति, समाज प्रकृति और सृष्टि का अध्ययन होता है और निष्कर्ष से समाज को एक-ाकार किया जाता है। चातुर्मास के इन प्रावधानों में मानो शरीर विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, मनोविज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ही नहीं अंतरिक्ष विज्ञान के निष्कर्ष को भी समाहित किया गया हे जो बात आधुनिक विज्ञान ने आज कही है उसके निष्कर्ष का क्रियान्वयन और भारतीय परम्पराओं के प्रचलन अनादिकाल से हो रहा है।

आधुनिक विज्ञान ने 19 वीं और 20 वीं सदर में

जाना कि मनुष्य चींटी से लेकर हाथी तक संसार के सभी प्राणी एक दूसरे के पूरक हैं और सृष्टि की नियामक शक्ति प्रकृति है। प्रकृति से समन्वय और संतुलन बनाकर ही धरती पर जीवन समृद्ध और दीर्घ जीवी होगा। यदि प्रकृति का क्षय होगा तो किसी का जीवन नहीं बचेगा। यह बात भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले खोज ली थी और इसकी सावधानियां ही इस चातुर्मास के आयोजन में हैं। इसे अनदेखा करके दुनिया ने विकास के नाम पर विनाश का मार्ग पकड़ लिया है। विज्ञान का दंभ भरने वाली दुनिया के सामने अब सत्य सामने आया है तो अब माग्र बदलने की छटपटाहट है। लेकिन भारत ने यह सावधानी और प्रकृति से समन्वय के साथ जीवन के संचालन का प्रावधान सैकड़ों हजारों

चातुर्मास की अवधि में उत्सव परंपरा को समझने के लिए तीन विषयों पर ध्यान देना होगा। एक मनुष्य की संरचना का रहस्य, दूसरा प्राणियों एवं वनस्पति का जीवन में उपयोगिता और तीसरा पुराणों में वर्णित कथाओं का संदेश।

साल से कर रखा है।

भारतीय वाड्म्य में चातुर्मास का विशेष महत्व है। यह आषाढ शुक्लपक्ष की एकादशी से आरंभ होता है। इसका समापन कात्रिक माह की शुल्कपक्ष की एकादशी को होगा। मान्यतानुसार, इन चार माह में भगवान नारायण पाताल लोक में विश्राम करते हैं, इसलिए कोई शुभ काम नहीं होते। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि यदि चातुर्मास में कोई पवित्र कार्य नहीं हो सकते तब सनातन परंपरा के सभी बड़े और महत्वपूर्ण त्योहार जैसे-गुरुपूर्णिमा, रक्षाबंधन, नागपंचमी, ऋषि पंचमी, गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, संतान सप्तमी, करवाचौथ, हरियाली अमावस, पितृपक्ष, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाईदूज इत्यादि सभी इसी अवधि में ही आते हैं।

चातुर्मास में होने वाली उत्सव परंपरा में वे सभी सावधानियां जिनमें व्यकित परिवार, समाज और राष्ट्र, अपना विकास तो करे पर प्रकृति का संरक्षण भी साथ साथ चले। हम जानते हैं कि प्राणी को भोजन, पानी, श्वास और आरोग्य सब प्रकृति से मिलता है। प्रकृति में जितने पदार्थ जिस अनुपात में हैं उसी अनुपात में मनुष्य देह के भीतर हैं और यह सभी पदार्थ पांच तत्वों से बने हैं ये हैं-धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। यदि प्रकृति में इनके अनुपात में परिवर्तन होगा तो इसका प्रभाव प्राणी देह पर भी पड़ेगा। इन चार महीनों में इन पांच तत्व के अनुपात में परिवर्तन आता है। यदि इस परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को सक्षम न किया तो यह अवधि मनुष्य को रोग ग्रस्त बना देती। चातुर्मास में भारतीय उत्सवों में न केवल इस अवधि के परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को सक्षम बनाना है अपितु इतना समृद्ध बनाना है कि फिर वर्ष भर तक कोई परिवर्तन व्यक्ति न कर सकेगा। इन चार माहों की त्योहार परंपरा का नियमन करने पर मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षमता तो आती ही है इसके अतिरिक्त उसका दृष्टिकोण सकारात्मक और सद्भाव से भरा होगा।

भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक के लिए तैयार होगा मसौदा

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहां देश में करीब चार लाख से अधिक लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे। फिलहाल उनकी संख्या बढ़कर करीब सात लाख पहुंचने का अनुमान है। भिखारियों की संख्या बढ़ने का यह अनुमान केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने को लेकर शुरू किए गए अभियान के दौरान लगा है। शहरों में इस अभियान को शुरू करने से पहले इनका सर्वे कराया गया था। हालांकि यह योजना मौजूदा समय में करीब 30 शहरों में चलाई जा रही है जिसका लक्ष्य 2026 तक भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने का है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आठ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। सिफारिश के मुताबिक केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को नगर निगमों और सरकारी एजेंसियों की सहायता से भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनाने की सलाह दी गई है। आयोग ने भीख मांगने में लगे लोगों के संरक्षण और पुनर्वास पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने की सिफारिश की है, ताकि लक्षित वित्तीय सहायता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, गरीबी उन्मूलन निरन्तर निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ रोजगार के अवसरों सहित उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर कार्यान्वित किया जा सके। आयोग ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा हेतु डिजिटल प्रिंट मीडिया में जागरूकता अभियान शुरू कर संघटित जबरन भीख मांगने की समस्या को सभी रूपों में समाप्त किया जाए। संघटित समूह अकसर कमजोर बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य करते हैं, कुछ मामलों में बच्चों को भीख के लिए मजबूर करने हेतु उनका अपहरण तक कर लिया जाता है। जबरन भीख मांगने के किसी रैकेट (दस्ते) पर अंकुश लगाने के लिए मानव व्यापार विरोधी कानून बनाने के लिए एक समाजशास्त्रीय और प्रभाती आर्थिक मूल्यांकन जरूरी है। इस कानून में अपराधियों के खिलाफ दण्डात्मक काररवाई सुनिश्चित हो। आयोग ने इस समस्या के समग्र समाधान हेतु सामाजिक कल्याण हस्तक्षेप, बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, अधिकारों की रक्षा और समाज में फिर से शामिल करने में मदद हेतु मजबूत कानूनी ढांचा बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आयोग के अनुसार, भीख मांगने के कारणों को सामने लाने के लिए भिखारियों के सर्वेक्षण, पहचान, मानचित्रण और डेटा बैंक तैयार करना, भिक्षावृत्तियों में लगे लोगों का पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कानूनी और नीतिगत ढांचा, गैर-कानूनी संघटनों, नागरिक समाज संघटनों, निजी क्षेत्र, धर्मार्थ ट्रस्टों इत्यादि के साथ सहयोग, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, जागरूकता पैदा करना एवं निगरानी की जाए।

अब देश में भीख मांगने पर रोक लगेगी, क्योंकि उनके संरक्षण और पुनर्वास के लिए कोशिश होगी। देश में भिक्षावृत्ति बढती जा रही है और रोकने की कोई ठोस पहल नहीं हुई है। हालांकि भिक्षावृत्ति के खिलाफ कुछ राज्यों में कानून भी बने हैं लेकिन वे इसे रोक पाने में अक्षम ही साबित हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केन्द्र और राज्य सरकारों को भिखारियों की स्थितियों में सुधार एवं पुनर्वास की सिफारिश की है।

आयोग के महासचिव भरत लाल ने कहा है कि भिक्षा में लगे लोगों की मौजूदगी कमजोर समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। भिक्षावृत्ति का कारण सिर्फ गरीबी नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक समस्या है जहां शिक्षा और रोजगार से वंचित लोग अपनी आजीविका के लिए भीख मांगने को मजबूर होते हैं। शहरों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर भीख मांगने वालों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, किन्नर, बुजुर्ग और दिव्यांग होते हैं। देश में भीख मांगना एक अहम सामाजिक समस्या रही है, जिसके पीछे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और दिव्यांगता आदि वजहें हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जहां देश में करीब चार लाख से अधिक लोग भिक्षावृत्ति से जुड़े हुए थे। फिलहाल उनकी संख्या बढ़कर करीब सात लाख पहुंचने का अनुमान है। भिखारियों की संख्या बढ़ने का यह अनुमान केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से शहरों को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने को लेकर शुरू किए गए अभियान के दौरान लगा है। शहरों में इस अभियान को शुरू करने से पहले इनका सर्वे कराया गया था। हालांकि यह योजना मौजूदा समय में करीब 30 शहरों में चलाई जा रही है जिसका लक्ष्य 2026 तक भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाने का है।

आयोग का कहना है कि भिक्षावृत्ति में लिप्त लोगों की पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उन्हें शहरों या जिलों में स्थित आश्रय गृहों में लाया जाय। उन्हें निवासियों के रूप में पंजीकृत किया जाए तथा राज्यों-संघ, राज्य क्षेत्रों या अधिकृत एजेंसियों में संबंधित विभागों, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों, द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएं, आश्रय गृह उन्हें आवास और भोजन की सुविधा, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा, आधार कार्ड, राशनकार्ड और बैंक खाते खोलने में सहायता सहित अन्य जरूरी सेवाएं मुहैया करे।

सुनिश्चित करें कि भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास की प्रक्रिया हेतु मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, नशामुक्ति और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करें। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के तहत सरकारी या निजी स्कूलों में भीख मांगने में शामिल 6-14 वर्ष की आयुवर्ग के सभी बच्चों को पंजीकृत और नामित किया जाय। साथ ही सम्मान से जीने के लिए कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही सरकारी तंत्र भिखारियों को उनके हकों के बारे में जागरूक करने के लिए एक जनसंपर्क और मोबिलाइजेशन सिस्टम स्थापित करे ताकि उनका शोषण रोका जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, गैर -सरकारी संघटनों और मानव अधिकार संरक्षकों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाए।

छुट्टा गाय एक सप्ताह में छह से अधिक लोगों को कर चुकी है घायल

कानपुर(जीकेबी)। गाय द्वारा बच्चे और महिला को सींग मारकर घायल कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस के साथ एडीओ पंचायत सुरेश निगम मौके पर पहुंचे और गाय को पकड़कर कैटिल वाहन से गोवंश आश्रय स्थल भेजा गया। कानपुर में सेन पश्चिम पारा थानाक्षेत्र के गढ़ेवा मोहसिनपुर गांव में शनिवार देर शाम बकरी चराकर घर लौट रहे 10 वर्षीय बच्चे को एक छुट्टा गाय ने सींगों में फंसाकर पटक दिया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि सुबह के समय एक महिला को भी गाय ने सींग मारकर घायल कर दिया था। बीते एक सप्ताह में गाय गांव के आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर चुकी है। गढ़ेवा मोहसिनपुर निवासी संतोष सविता का 10 वर्षीय बेटा अनुराग शनिवार देर शाम खेत से बकरी चराकर वापस लौट रहा था। गांव किनारे एक छुट्टा गाय और एक आवारा सांड़ आपस में लड़ रहे थे। अचानक गाय ने बच्चे को सींगों से उठाकर सड़क पर पटक दिया, जिससे उसके चेहरे और हाथ में गंभीर चोटें आईं। बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने लाठी-डंडा लेकर गाय को भगाया। बच्चे को गल्ला मंडी स्थित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके पहले शनिवार सुबह गाय ने राजकुमार की पत्नी गायत्री (38) को सींग मारकर घायल कर दिया था। वह घर से कूड़ा डालने जा रही थी। सूचना पर पुलिस के साथ एडीओ पंचायत सुरेश निगम मौके पर पहुंचे और गाय को पकड़कर कैटिल वाहन से गोवंश आश्रय स्थल भेजा गया।

परिवार के लोग आप के घर आने की राह देख रहे हैं

कम उम्र में बच्चों को दो पहिया (मोटर साइकिल),चार पहिया आदि चलाने देना यूँ तो यातायात नियम के विरुद्ध कार्य है ।वही जान माल की हानि की सम्भावना बनी रहती है ।बच्चों को गाड़ी चलाने देना आजकल फैशन सा बन गया यदि बच्चा गाड़ी चलाता है तो माता- पिता अपनी शान समझते है जब दुर्घटना होती या चालान बनता है तब लोग बाग ही ताना देने लग जाते है कि बच्चों को ज्यादा ही सर चढ़ा रखा था ।साथ ही दुर्घटना होने पर भविष्य के निर्धारित किये लक्ष्य भी पिछड़ से जाते है ।गाड़ी चलाने की अनुमति वयस्क होने के बाद ही देना चाहिए वाहनो की गति सीमा जो शहरों,गांवों में निर्धारित है उसकी सूचना के बोर्ड लगाये जाना चाहिए गति सीमा का पालन नहीं होने से सड़क दुर्घटनाओ में बढ़ोतरी होती है ।गति सीमा से अधिक चलते वाहनो पर अंकुश आवश्यक है` साथ ही यातायात के नियमो का पालन हेतू कम से कम तहसील स्तर पर चौराहों पर जहाँ ज्यादा वाहनों का आवागमन हो वहाँ पर सिंग्नल लगाये जाना चाहिए ताकि यातायात जाम होने की परेशानी न उठाना पड़े ।सड़क पर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे लोगो की आए दिन दुर्घटना की खबर पढ़ने को आती है ।अधिकांश लोग वाहन चलाते समय चालक अपने मोबाइल को कान और कंधे के बीच दबा बातचीत करते हुए वाहन चलाते है उनका ध्यान बातचीत पर ही ज्यादा रहता हैं ।पीछे हार्न देने वाले की भी वो सुनते नहीं ऐसे में दुर्घटना संभव है । जरुरी बात भी करना होतो थोड़ा सा ठहर के बात करना चाहिए ।कई लोग मोबाइल पर बातचीत जोर-जोर से करते है। इससे पास बैठे लोगो को बातचीत करने में व्यवधान होता है और सुनाई ना देने की परेशानी उठानी पड़ती है ।मोबाइल एवं स्वयं की सुरक्षा के साथ दूसरों का भी ख्याल रखे। सीमा से अधिक चलते वाहनो पर अंकुश आवश्यक है` साथ ही यातायात के नियमो का पालन हेतु कम से कम तहसील स्तर पर चौराहों पर जहाँ ज्यादा वाहनों का आवागमन हो वहाँ पर सिंग्नल लगाये जाना चाहिए ताकि यातायात जाम होने की परेशानी न उठाना पड़े ।सड़क पर चलते हुए या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात कर रहे लोगो की आए दिन दुर्घटना की खबर पढ़ने को आती है ।मोबाइल एवं स्वयं की सुरक्षा के साथ दूसरों का भी ख्याल रखे। परिवार के लोग आप के घर आने की राह देख रहे है। सुरक्षित चले ।साथ ही तेज गति ,करतबों और ,निर्धारित सीट से ज्यादा न बिठाने संबधी हिदायत देना भी बच्चों के हित में उचित कदम होगा। सुरक्षित चले।

संजय वर्मा "दृष्टि"
मनावर जिला-धार

नीरज साहित्य समूह द्वारा साझा संकलन 'कभी तेरी आरजू में' के विमोचन के अवर पर कविगण व अन्य

साहित्य समूह का कवि सम्मेलन एवं पुस्तक विमोचन कार्यक्रम संपन्न

नई दल्ली । द्वारका डी 21 स्टूडियो दिल्ली में नीरज साहित्य समूह की ओर से भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ नीरज साहित्य समूह द्वारा साझा संकलन 'कभी तेरी आरजू में' के विमोचन के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया ।साझा संकलन का विमोचन मुख्य अतिथि अन्तर्राष्ट्रीय ओज के कवि श्री अर्जुन सिसोदिया जी ने किया ।कवि सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए कवियों ने समाँ बांधा।अपनी प्रस्तुतियों द्वारा लोगों का मन मोह लिया ।कवियों का काव्य पाठ इतना मोहक था कि श्रोता स्थान पर बने रहे ।कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि अन्तर्राष्ट्रीय कवि श्री अर्जुन सिसोदिया जी रहे ।दिल्ली,हरियाणा उत्तर प्रदेश,हिमाचल प्रदेश राजस्थान ,उत्तराखंड से कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया। कवि सम्मेलन का लाइव प्र-सारण किया गया। कवि सम्मेलन को मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुरूआत की ।छोटे छोटे बाल कलाकारों ने सरस्वती वन्दना गीत प्रस्तुत करके माँ शारदे का स्मरण किया ।उपस्थित कवियों में अर्जुन सिसोदिया ने वीर रस पूर्ण रचना चन्द्र शेखर के बारे में पढ़कर श्रोताओं मे जोश भर दिया, प्रसिद्ध गजलकार संजय जैन ने **शहीद की माँ के उदगार** बेटे ने पूछा माई कहकर श्रोताओं की आँखें नम कर दी।

नीरज साहित्य समूह के अध्यक्ष एवं कवि अशोक आबशार ने तुम्हारी भी कोई कहानी तो होगी गजल द्वारा मन मोहा,कवि डॉ नाथू लाल लोटवाड़ा ने 'गजल **वो बिछड़ा पर आँख मिलाकर नहीं गया**' द्वारा मन मोहा,कवयित्री सीमा रंगा ने **बचाया है शहीदों ने तभी तो आज जिंदा है** प्रस्तुत कर सबको जोड़ा।

रामेश्वर देव ने देशभक्ति के मुक्तको द्वारा मन मोहा,उर्वी उदल ने 'मुझे पागल ने सिर पर चढ़ा रखा है' द्वारा समा बांधा,सरिता जैन ने ह्रगांर की रचनाओं द्वारा सबको गुदगुदाया,सीमा वत्स ने ह्रनयन के नीर से लड़ना ह्रमुक्तक गा कर श्रोताओं को मोहा,गीता राघव द्वारा कृष्ण की आरजू कविता पढ़कर मन मोहा,नीरज साहित्य समूह की सचिव रचना भारद्वाज ने **कभी तेरी आरजू में दिया जलाते रहे** कविता पढ़कर सबका मन मोहा ।नीरज साहित्य समूह द्वारा सभी को पटका पहनाकर एवं मोमंटो दे कर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन का संचालन वर्षा सिंह द्वारा किया गया।

सपने, ख्वाब, मान, तिरस्कार

नहीं रहा अब इनसे कोई सरोकार
नफरतों की दुनिया में
प्रेम बन गया जबसे एक कारोबार
माँग का सिंदूर हुआ करता था प्यार
मंगलसूत्र का बंधन था विश्वास का सार
दौलत की चाहत में अब
दौलत ही बन गयी प्यार का आधार
गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर
परिंदों को कैद कर झूठा दिखाते लाड़ प्यार
धनवानों की नजर में पिंजरा ही बन गया
जैसे आज सुखी जीवन का संसार

वर्षा वार्ष्णेय

घूँघट की बगावत

21 जुलाई 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

8

मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा फैसला

क्या है मामला-

अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में इसने दलील दी थी कि तलाकशुदा महिला सीआरपीसी की धारा-125 के तहत याचिका दायर कर सकती है। ऐसा ही फैसला 1985 में शाहबानो केस में सुनाया गया था। यह फैसला शाहबानों केस की याद ताजा कर गया। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 में मुस्लिम महिलाओं को भी पति के भरण पोषण पाने का अधिकार है। देश की मुस्लिम महिलाओं ने जहां एक ओर इस फैसले का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और फैसले को मुस्लिम महिलाओं के हक में बताया पहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे शरीयत के विरुद्ध बताया है। इस संदर्भ में मौलानाओं का कहना है कि तलाक के बाद शरीयत में सिर्फ तीन महीने तक भरण पोषण भत्ते का अधिकार है। उसके बाद बीवी की जिम्मेदारी शौहर की नहीं बनती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे बड़ा व्यापक असर हमारे समाज पर पड़ेगा। उन्होंने दलील दी कि अगर शौहर के पास पैसे नहीं हैं तो वह गुजारा भत्ता किस तरह दे सकता है। इसी के साथ कहा कि इससे तलाक के मामले कम होंगे और गुजारा भत्ता बचने के लिए पुरुष तलाक नहीं लेंगे।

गैर-भाजपा दलोंने जब कभी मुसलमानों की भलाई का मौका आया तब नजरें चुरा लीं, बल्कि सत्ता में आने पर पुरानी स्थिति बहाल करने तक का वादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125 की मदद ले सकती हैं। यह कानून सभी धर्म की महिलाओं पर लागू होता है। गुजारे भत्ते के लिए अपने पति के खिलाफ याचिका दायर कर सकती हैं।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टाइन गॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया। इस फैसले को गैर-भाजपा दल गले नहीं उतार पा रहे हैं। इसी तरह तीन तलाक के फैसले को लेकर कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने विरोध किया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये तीन तलाक के फैसले को पलट कर वापस तीन तलाक लागू करने का वादा किया था। इससे पहले शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कानून में संशोधन करके बदल दिया था। कांग्रेस ने यह सब किया वोट बैंक की खातिर, किन्तु वह बच नहीं सका। दूसरे दल मुसलमानों की भलाई की आड़ में अपना उल्लू सीधा करने में ज्यादा आगे निकल गए। गैर-कांग्रेस दलों में प्रमुख रूप से पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम वोटों की खातिर आतंकवाद के आरोपियों से समझौता तक करने में गुरेज नहीं किया। शाह बानो केस में राजीव गांधी की सरकार ने वोट बैंक की खातिर कोर्ट का फैसला बदल दिया था।

शाहबानो ने 1978 में इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि उनके पति को उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए निर्देश दिया जाय। साल 1985 सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानों के पक्ष में निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अब्दुल को अपनी तलाकशुदा बीवी को बीस हजार रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था। समद ने अपनी बीवी को तीन तलाक दिया था। इसके जवाब में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों के संरक्षण) अधिनिम-1986 लागू कर दिया। इस अधिनियम ने तलाक के बाद केवल 90 दिनों तक मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इसी प्रकार मुस्लिमों की आधी आबादी के पक्ष में जब तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया तब भी गैर-भाजपा दलों ने काफी हाय-तौबा मचाई थी। सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की संविधानपीठ ने 22 अगस्त 2017 को अपने फै सले में ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया

था। कोर्ट ने 1400 साल पुरानी प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था और सरकार से कानून बनाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केन्द्र सरकार ने कानून बनाते हुए एक साथ तीन बार तलाक बोलकर या लिखकर निकाह खत्म करने को अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया। इस अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष कैद की सजा का प्रावधान भी है। तीन तलाक के मुद्दे पर गैर-भाजपा दलों का असली चेहरा उस वक्त सामने आया जब संसद में इसके मामले में कानून पास करने से पहले वोटिंग हुई। गैर-भाजपा दल ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे, लेकिन राज्य सभा में वोटिंग के पहले भाग गए। इनमें बसपा के चार, सपा के सात, एनसीपी के दो, पीडीपी के दो, कांग्रेस के पांच, टीएमसी, वामपंथी पार्टियों, आरजेडी, डीएमके और वाइएसआर कांग्रेस के एक-एक सांसद अनुपस्थित रहे।

कांग्रेस के अल्पसंख्यक महाधिवेशन में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो नरेन्द्र मोदी सरकार के लाए ट्रिपल तलाक कानून को खत्म कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि ये कानून मुस्लिम पुरुषों को जेल में भेजने की साजिश है। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता एक लफ्ज तक नहीं बोला। तीन तलाक पर पाबदी का फैसला हो या मेंटीनेंस पाने का हक, मुस्लिम आधी आबादी लम्बे अर्से से अपने अधिकारों के प्रति अंधेरे में रही है। उलेमाओं और मौलवियों ने ऐसे अधिकारों का हमेशा से विरोध किया है।

वोट बैंक के लालच में कांग्रेस सहित दूसरे दलों ने हमेशा मुसिलम महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने की पैरवी की है। यदि ये दोनों अधिकार कांग्रेस आजादी के बाद मुस्लिम महिलाओं को कानूनी तौर पर मुहैया करा देती तो आज देश में मुसलमानों के विकास की सूरत अलग होती।

किसी भी शिक्षित और जागरूक कौम को आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। गैर-भाजपा विपक्षी दलों ने मुसलमानों को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यहां तक कि मुसलमानों के खैरख्वाह बनने का दंभ भरने वाले राजनीतिक दलों ने उन्हें राजनीति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया। यही वजह रही कि आजादी के बाद जितनी तरक्की मुसलमानों को करनी चाहिए थी उसकी तुलना में पिछड़ गए। मुसलमानों केविकास के सपने धराशायी हुए। बिल को पास कराने के लिए एनडीए की 121 सदस्यों का समर्थन चाहिए था लेकिन सांसदों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति की वजह से सदर में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और वह बिल पास कराने में सफल रही। विपक्ष के भागने की वजह यह रही कि भाजपा इसे मुद्दा बनाकर मुस्लिम महिलाओं से उसके खिलाफ धरना-प्रदर्शन नहीं करवा दे। बिल पर बहस के दौरान वाइएसआर कांग्रेस के विजय साई ने कहा कि बिल का मैं छह कारणों से विरोध करता हूं। लेकिन वोटिंग के दौरान विजय साई सदन में अनुपस्थित थे। बसपा सांसद सतीश चंद मिश्र का कहना था कि हमारी पार्टी इस बिल के खिलाफ है। और इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए था। उनहोने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे नकार दिया है और आप फिर से इसे अस्तित्व में लाना चाहते है। इस बिल से महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली हैं, क्योंकि पुरुष के जेल जाने के बाद महिलाएं भी कहीं की नहीं रह जाएंगी। सरकार न बच्चों की देखरेख करेगी और न ही महिलाओं को गुजारा भत्ता देगी, ऐसे में उनका जीवन कै से चलेगा। तीन तलाक पर इस तरह मुखर होने के बावजूद बसपा का कोई सांसद सदन में उपस्थित नहीं था। एनसीपी माजिद मेनन ने इस बिल का विरोध किया था। उन्होने कहा था कि आप किसी को बिना अपराध के तीन साल की सजा देने जा रहे हैं, तलाक कहना कोई अपराध नहीं है। जेल जाने के बाद शादी खत्म नहीं होगी और महिला को गुजारा भत्ता पाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। जेल में रह रहा पति कै से पत्नी को भत्ता दे पाएगा। ऐसे में कानून फेंक हो गया है। यह बिल पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। परन्तु जब बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए सदन में वोटिंग हो रही थी उस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल उपस्थित नहीं थे। तीन तलाक बिल का विरोध करने वाले एनडीए के सहयोगी दल तो वॉकआउट कर गए, जिनमें अन्नाद्रमुक जेडीयू शामिल हैं। गैर-एनडीए और गैर-यूपीए टीआरएस सदन में गैर-मौजूद रहीं। ''सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता दान का मामला नहीं है बल्कि विवाहित महिलाओं का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान में हर धर्म की महिला को समान हक देने का कानून है। इसलिए मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता पाने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य धर्म की महिलाओं को है।

16 लाख भारतीय बच्चे जरूरी टीके लेने से चूके: यूनिसेफ

बच्चों में टीकाकरण रिकॉर्ड को सुधारने के लिए कैच-अप अभियान शुरू करने के बावजूद, 2023 में खसरा और डीपीटी के टीके 3,50,000 से अधिक बच्चों को नहीं दिए जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण कवरेज 2023 में रुक गया, जिससे 2019 में महामारी से पहले स्तर की तुलना में 27 लाख अतिरिक्त बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने दुनिया भर में टीकाकरण को लेकर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के तीन साल बाद भी भारत में बच्चों के टीकाकरण का स्तर अभी भी महामारी से पहले के स्तर पर नहीं पहुंचा है। यह इसलिए कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2023 में 16 लाख बच्चों को डीपीटी और खसरे के टीके नहीं लग पाए। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 की तुलना में 2022 में हुई बढ़त एक साल बाद थम गई है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत के बच्चों में टीकाकरण रिकॉर्ड को सुधारने के लिए कैच-अप अभियान शुरू करने के बावजूद, 2023 में खसरा और डीपीटी (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस) के टीके 3,50,000 से अधिक बच्चों को नहीं दिए जा सके।

2023 में 16 लाख शून्य-खुराक वाले बच्चे 2022 में 11 लाख ऐसे बच्चों की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक हैं, लेकिन पिछले दो महामारी वाले सालों की तुलना में काफी कम हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण कवरेज 2023 में रुक गया, जिससे 2019 में महामारी से पहले स्तर की तुलना में 27 लाख अतिरिक्त बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए।

डब्ल्यूएचओ ने डेंगू के नए टीके को दी मान्यता, 54 महीनों तक डेंगू बुखार से सुरक्षा का दावा

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का टीकाकरण कवरेज 2020 और 21 के महामारी वर्षों में काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन तब से यह एक उत्साहजनक प्रक्षेपवक्र पर है।

2023 की उपलब्धि अभी भी 2019 से थोड़ी कम है। साल 2023 की उपलब्धि भी 2022 की तुलना में थोड़ी कम है, लेकिन यह एक ऐसा पैटर्न है जिसे कई देशों में देखा गया है। रिपोर्ट में सुझाव देते हुए कहा गया है कि जो बच्चे 2021 में टीका लेने से चूक गए थे, उन्हें एक साल बाद खुराक दी गई।

संयुक्त राष्ट्र की दोनों एजेंसियों ने भारत को उन 52 देशों में शामिल बताते हुए इस बात पर आपत्ति जताई है, जिन्होंने अपने टीकाकरण पैकेज में एचपीवी टीकाकरण को शामिल नहीं किया है, जबकि गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर महिलाओं में कैंसर का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, जो महिलाओं में होने वाले कैंसर का लगभग 18 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण कवरेज 2023 में रुक गया, जिससे 2019 में महामारी से पहले स्तर की तुलना में 27 लाख अतिरिक्त बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए।

50 वर्षों के दौरान समय पर टीकाकरण से बच गई 15 करोड़ जानें

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण कवरेज 2023 में रुक गया, जिससे 2019 में महामारी से पहले स्तर की तुलना में 27 लाख अतिरिक्त बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए। भारत, नाइजीरिया, कांगो, इथियोपिया, सूडान और पाकिस्तान के साथ शून्य खुराक वाले बच्चों की सबसे कम संख्या वाले दुनिया के दस सबसे खराब देशों में से एक है। सहस्राब्दी की शुरूआत से लेकर 2019 तक देश के टीकाकरण कवरेज में लगातार सुधार हुआ, जब महामारी ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अधिकांश नियमित स्वास्थ्य सेवाएं ठप्प हो गई। 2020 में, राष्ट्रीय कार्यक्रम में 25 से 34 लाख बच्चों को डीपीटी और खसरे के टीके नहीं लग पाए, लेकिन 2021 और 2022 में संख्या में सुधार हुआ, लेकिन 2023 में इसमें फिर से गिरावट देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी ने दुनिया भर में टीकाकरण की प्रगति को बुरी तरह बाधित किया है, जिससे दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियां पीछे चली गई हैं। नवीनतम आंकड़े डीटीपी कवरेज में चिंताजनक ठहराव और 'शून्य खुराक' वाले बच्चों की बड़ी संख्या को दशार्ते हैं जो महामारी से पहले के स्तर से अधिक हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बच्चों के टीकाकरण कवरेज 2023 में रुक गया, जिससे 2019 में महामारी से पहले स्तर की तुलना में 27 लाख अतिरिक्त बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए।

मलेरिया के टीके का असर जल्दी खत्म क्यों हो जाता है: शोध

रिपोर्ट से जुड़े महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ ने रिपोर्ट के हवाले से कहा, हमारे देश के नजदीक, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र जिसमें भारत भी शामिल है, में डीटीपी1 कवरेज में दो प्रतिशत की गिरावट देखी गई है और लगभग 35 लाख बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं (डीटीपी3 औरडीटीपी1) से बाहर हो गए हैं। कमजोरी और संघर्ष का सामना करने वाले क्षेत्रों में टीकाकरण से बाहर होने वाले बच्चों और कवरेज की संख्या और भी अधिक है। यह जरूरी है कि देश तत्काल कैच-अप टीकाकरण अभियानों को फिर से प्राथमिकता दें और उनका दायरा बढ़ाएं।

लड़कियों के बीच वैश्विक एचपीवी वैक्सीन कवरेज में काफी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में टीकाकरण के नए आंकड़ों को भी सामने रखा गया है जिसके मुताबिक, मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) के टीकाकरण में सुधार हुआ है। 57 देशों में मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी), मेनिन्जाइटिस, न्यूमोकोकल, पोलियो और रोटावायरस रोग सहित नए और कम उपयोग किए जाने वाले टीकों में विस्तार हुआ है। दुनिया भर में किशोर लड़कियों की हिस्सेदारी, जिन्होंने एचपीवी वैक्सीन की कम से कम एक खुराक हासिल की है, जो गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से सुरक्षा प्रदान करती है, 2022 में 20 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 27 प्रतिशत हो गई है।

गंडक में उतार-चढ़ाव जारी

पडरौना (जीकेबी)। गंडक के जलस्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है। मंगलवार को वाल्मीकिनगर गंडक बैराज पर 1 लाख 35 हजार 900 क्यूसेक डिस्चार्ज रहा। नदी भैंसहा गेज पर चेतावनी बिंदु से अभी भी 18 सेमी ऊपर बह रही है। जलस्तर में हो रहे उतार-चढ़ाव को देख रेताक्षेत्र के लोगों की सांसें अटकी हैं। बाढ़ का खतरा अभी भी रेताक्षेत्र से टला नहीं है। डिस्चार्ज में कमी होने से नदी सामान्य स्थिति में लौटने के साथ ही डाउन स्ट्रीम में कई जगहों पर कटान भी कर रही है। छितौनी तटबंध पर संवेदनशील बिंदुओं को निशाने पर लेकर नदी दबाव बनाना शुरू कर दी है। नदी के बैकरोलिंग से कई गांवों पर कटान का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश थमने के बाद बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में कमी होने लगी है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी डिस्चार्ज में कमी दर्ज की गई। मंगलवार को 1 लाख 35 हजार 900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। वहीं, नदी खड्डा के भैंसहा गेज पर चेतावनी बिंदु से 18 सेमी ऊपर बह रही है। इतने जलस्तर से फिलहाल रेताक्षेत्र के गांवों में बाढ़ का आशंका नहीं है। लोगों का कहना है कि फिलहाल उन्हें बाढ़ से राहत है। लेकिन, जिस तरह से नदी के जलस्तर में उतार-चढ़ाव हो रहा है, उससे अभी भी बाढ़ का खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। इसके अलावा जलस्तर में कमी होने के बाद डाउन स्ट्रीम में आई नदी छितौनी तटबंध के संवेदनशील बिंदुओं, स्पर सी व फार्क स्पर पर तेज दबाव बनाने लगी है। ठोकरों पर बनाए गए काउंटर वर्म लांच होने लगे हैं। हालांकि, काउंटर वर्म के लांच होने से बांध व ठोकरों पर कोई खतरा नहीं है। काउंटर वर्म इसलिए बनाए जाते हैं कि वह लांच होने के बाद ठोकरों को निचली सतह तक मजबूत बनाए रखें। नदी के बढ़ते-घटते जलस्तर पर बाढ़ खंड की टीम नजर रख रही है। दूसरी तरफ, रेताक्षेत्र के लोगों का कहना है कि इतने जलस्तर से गांवों में बाढ़ का पानी नहीं घुस सकता है। जलस्तर में उतार-चढ़ाव होने से बाढ़ का खतरा अभी भी बना हुआ है।

विश्वसमाज आज डर के माहौल में जीने को मजबूर

विश्व सामजिक न्याय दिवस हमें प्रत्येक वर्ष अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समतापूर्ण समाज बनाने की जरूरत को याद दिलाता है। समाज को समर्थ बनाने की दिशा में इस दिवस का विशेष महत्व है। साथ ही समाज से असमानता, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार होना भी है। आज, जरूरी है कि विश्व समाज में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय बिना किसी भेदभाव के देरी और निष्पक्ष सभी को न्याय मिले। मौजूदा दौर में दुनिया के ज्यादातर देशों में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी न्याय समय और बिना किसी भेदभाव के मिलना दूभर हो गया है। जातिगत, वर्गगत, और क्षेत्रगत जैसे भेदभाव को मिटाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। विधि के क्षेत्र में न्याय के जिन चार प्रकारों की बात की जाती है उनमें वितरणात्मक (यह निर्धारित करना कि किसे न्याय मिलता है)प्रक्रियात्मक न्याय (यह निर्धारित करना कि लोगों के साथ कितना निष्पक्ष न्याय व्यवहार किया जाता है) प्रतिशोधात्मक न्याय (गलत काम करने पर दण्ड के आधार पर) और पुनर्स्थापनात्मक न्याय (जो रिश्तों को सही बनाने की कोशिश करता है) इन चार प्रकार के न्याय को समझना और दूसरों को इनके प्रति जागरूक करना भी इस दिवस का एक हिस्सा है। जाहिरतौर पर, न्याय के लिए जरूरी है कि प्राकृतिक कानून, तर्क संगत विचार, कानून, धार्मिक सिद्धान्त, नैतिकता, निष्पक्षता और समानता के स्तर पर सबको न्याय उपलब्ध हो। दुनिया के करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। वैश्विकस्तर पर मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध आवाज उठाइ जाती है, लेकिन यह अपवाद की भांति ही है। विकसित और विकासशील देशों में बड़े पैमाने पर लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन के समाचारों से यह पता चलता है कि जिस न्याय की अवधारणाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व न्यायालय ओर दूसरी तमाम संस्थाएं जिस प्रकार सक्रिय

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों, संघटनों और व्यक्तियों से एक से ज्यादा न्यायपूर्ण और समतापूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करने और दुनिया में शांति, सुरक्षा और सर्वहित के खतरा बने अपराधियों के खिलाफ मानवतावादियों की एकजुटता का यह पहल कई नजरिये से खास कही जा सकती है।

रहती हैं अथवा देखने को मिलती हैं वैसा न्याय नहीं दखने को मिलता है। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सजा पाए अपराधी सुधार प्रक्रिया में कहीं सक्रिय नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार दुनिया की सभी न्यायवादी संस्थाओं को गैर करना आवश्यक है।

दुनिया में जिन गैर-इंसानी कवायदो से सामाजिक जिंदगी में तनाव और दुश्वारियां बढ़ी हैं, उनमें अन्याय प्रमुख माना जा सकता है। न्यायालयों से मिलने वाला न्याय अधिकांशतः इतने विलम्ब के साथ मिलता है कि वह अन्याय से अधिक परेशान करने वाला होता है। इसलिए वक्त और अधिकार की सीमा में न्याय सभी को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जा सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रकरण हों अथवा भेदभावों की वजह से जुल्म-ओ-सितम सह रहा व्यक्ति हो, पुलिस के जुल्म का मामला हो या परिवार में हिंसा का मामला, न्याय सहज रूप से प्रताडित को बिना किसी विलम्ब के प्राप्त हो यह भी न्यायदिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। विकासशील देशों में ही अन्याय के मामले अधिक नहीं हैं, बल्कि विकसित देशों में अन्याय से पीड़ित लाखों की संख्या में लोग हैं। भारत में करोड़ों की तादाद में न्यायालयों में मुकदमे लंबित हैं। करोड़ों मुकदमों का निर्णय तब आता है जब वादी या प्रतिवादी इस दुनिया से ही रुख्सत हो चुका होता है। न्यायदिवस अन्य दिवसों की तरह आए और चला जाए, ऐसा इस दिवस के साथ नहीं होना चाहिए बल्कि बिना किसी भेदभाव के न्याय दिलवाने और समय से दिलवाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास तो होने ही चाहिए। संविधि में शामिल सभी देशों को एक मत से इस बात पर गौर करना चाहिए कि सभी अपना देशों में न्याय को बिना किसी भेद भाव और समय के अन्दर मिले, इससे इस दिवस की प्रासंगिकता और महत्व भी बढ़ जाएगा।

नरसंहार युद्ध अपराध रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। 17 जुलाई, 1998 को 120 देशों ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि नामक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। तब से स्थापना को अंतरराष्टीयआपराधिक न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा, जो 1 जुलाई, 2002 को लागू हुआ। रोम संविधिका जश्न मनाने के लिए, विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस तब से मनाया जाने लगा। पिछले 22 वर्षों में दुनिया में न्याय के क्षेत्र में तमाम बदलाव आए हैं। नरसंहार मानवीय मूल्य के हनन, मानवता के खिलाफ दुनिया में चलाए जा रहे तमाम षड्यंत्रों को विफल करने में इस संस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना के पीछे नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ किए जा रहे अपराधों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के निर्णयों का समर्थन करना भी है। विश्व अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक वैश्विक प्रयास के रूप में देखा और समझा जाता है। वर्ष 2010 में राज्य दलों की सभा ने संविधि की समीक्षा सम्मेलन में इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निश्चय किया। तब से लगातार 17 जुलाइ को प्रतिवर्ष इसे मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम देश इसे मनाते हैं और युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ दुनिया में चल रहे तमाम गतिविधियों की समीक्षा करने और इन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा भी करते हैं। दुनिया में नयाय के समर्थकों को एकजुट करना और पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना इस दिवस के मनाने के पीछे की खास वजह रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों, संघटनों और व्यक्तियों से एक से ज्यादा न्यायपूर्ण और समतापूर्ण विश्व के लिए मिलकर काम करने और दुनिया में शांति, सुरक्षा और सर्वहित के खतरा बने अपराधियों के खिलाफ मानवतावादियों की एकजुटता का यह पहल कई नजरिये से खास कही जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कानून, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष समाज की जरूरत आज विश्व समाज की सबसे बड़ी जरूरत है जो आतंक, नरसंहार और गैर-इंसानी गतिविधियों के शिकार हो हलाकानी झेलने के लिए अभिशप्त हैं। विश्व समाज आज जिस डर के माहौल में जीतने को मजबूर है वह कई दुश्वारियों को झेलने के लिए भी मजबूर है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोशिशों की भूमिका खास मायने रखती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com